from all sections of the House saying that they would like to have a full debate on the price situation. Therefore, I am converting the Calling Attention into a short duration discussion.

SHRI M. KALYANASUNDARAM (Tamil Nadu): Sir, I make a submission? I would like to raise a matter in regard to the Central Government employees.

MR. CHAIRMAN: No. Not permitted. Mr. Chaturanan Mishra to move the Calling Attention Mouon. *yu:tcn;ip-tions)* Nothing else will *go* on record, I am not allowing this.

SHRI M. KALYANASUNDARAM:*

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra) :*

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu):*

MR CHAIRMAN: : I will not allow this, I consider all these matters in my chamber and whatever is urgent and important,, I allow. This is not such an urgent thing and this has not been raised in my chamber. Therefore, I am not allowing it. I am not going to deviate from this practice. Mr. Chaturanan Mishra please. Nothing else will go on record. No Zero Hour.

SHRI M. KALYANASUNDARAM: What is the remedy then?

MR. CHAIRMAN: Next day.

SHRI M. KALYANASUNDARAM: I will not be there.

MR. CHAIRMAN: If you are not here, other Members are there.

The House cannot adjust itself to the convenience of individual Members. No.

SHRI M. KALYANASUNDARAM; H this is what you say, I am i» your hands. I am helpless.

*Not ricird-d as ord^rd by the Chiir.

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. I know, you will co-operate with me.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Sir, do you deny the existence of Zero Hour in this House?

MR. CHAIRMAN: I am not here to answer questions. I go according to the rules and practice. *(Interruptions)* I am co-operating more with you than you are co-operating with me.

SHRI M. KALYANASUNDARAM: My conscience does not permit me to submit to your arbitrary decision. I am walking out in protest.

SHRI S. W. DHABE: I support what Mr. Kalyanasundaram has said and I am also walking out.

SHRI V. GOPALSAMY: We also support Mr. Kalyanasundaram and we are walking out.

[At this stage, some hon. Members left the Chambers,}

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Situation arising out of steep rise in prices of Essential Commodities

MR. CHAIRMAN: Calling attention please.

SHRI CHATURANAN MISHRA (Bihar): Sir, I call the attention of the Minister of Food and Civil Supplies to the situation arising out of the steep rise in the prices of essential commodities and the steps taken by the Government in this regard.

MR. CHAIRMAN: Now, the hon. Minister will make the statement and after that, the discussion will take Place.

fLater converted into Short Duration Discussion.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI K. P. SINGH DEO): Mr. Chairman. Sir, Hon. Members are aware that there was some improvement in the overall price situation in 1984-85. The annual rate of inflation declined from 9.2 per cent in March, 1984 to 6 per cent in March, 1985. The annual rate of inflation has declined further to 4.8 per cent in the first week of November, 1985. During the first seven monies of the current financial year the Wholesale Pirce Index has moved up by less than 4.0 per cent. I may also inform the Hon'ble Members that during the past 13 weeks ending 2nd November, 1985, the Wholesale Price Index has moved down by 2.0 per cent. However, the prices of some essential commodities have moved up

The availability of essential com. modifies has been generally satisfactory. It is remarkable, Hon'ble Members will agree, that during the lean period and the festival season the supply position of various essential commodities including edible oils and sugar has been by and large satis, factors'.

We have not only attained self-sufficiency in foodgrains but are now having some surplus wheat. This has provided us the much needed food security. In fact, we are trying through various programmes, announced by the Finance Minister yesterday, to provide food to weaker and vulnerable sections of the society and cheaper prices.

Hon'ble Members may recall that su<?ar production has been sluggish during the past two years and we had to resort to substantial imports. In order to enable the sugar factories to pay remunerative prices for sugarcane, the statutory minimum price of sugarcane has been raised from Bs. 14 a quintal linked to recovery of 8.5 Per cent to Rs. 16.50 a quintal linked to recovery of 8:5 per cent for the current year and to Rs. 17 a quintal Unked to recovery of 8.5 per cent for I the next sugar year. As a conse-I quence the retail price of levy sugar has been raised by 40 Paise per kg. to be effective from the beginning of December, 1985JL It' is hoped that this will provide the necessary encouragement for enhancing the production of sugarcane and sugar so as to attain self-sufficiency.

In order to encourage domestic pro. duction and reduce our dependance on imports, the issue prices of imported edible oinls to the vanaspati industry and for the Public Distribution System have been raised by Bs. 2,000 per tonne and Rs. 1,000 a tenne respectively from 15th November, 1985. Simultaneously, the supply oi imported edible oils to the vanaspati industry has been reduced from 60 per cent of their requirement to 50 per cent. They have, however, been allowed to use expeller mustard/ rapeseed oil in lieu of this reduction. In view of this, the voluntarily agreed prices of vanaspati have been raised by the industry.

Government is exercising constant surveillance to keep the prices of es sential commodities in check. Every effort is being made to ensure their availability throughout the country. The main thrust of Government's po licy is to increase the production of essential commodities ptrticularly those in short supply. The. export of essential commodities particularly keeping in view our domestic requirements. Some commodities are imported in augment domestic supply. The Public Distribution System is being expanded and improved. The State Governments are inforcing the Essential Commodities Act and similar legislations.

श्री चतुरानन मिश्र: सभापति महोदय, मूल्य वृद्धि के कारण देश में एक असाधारण स्थिति पैदा हो गयी है। यह स्थिति जब से पिछला बजट आया है उसके बाद से ही शुरू हुई है। अभी मंत्री महोदय ने कुछ आइटम्स के बारे

[श्री चतुरानन मिश्र]

में कहा कि इनमें चीजों की कमी हो रही है। इस पर मैं बाद में आऊंगा लेकिन स्थिति यह है कि पिछले 2 वर्ष ऐसे रहे जब कि गल्ले का रिकार्ड प्रोडक्शन हुआ, 83-84 में और उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन कमोबेश इस साल वही स्थिति रही। प्रोक्योरमेन्ट भी फूड का बहुत अच्छा होता रहा। इतना अच्छा कि सरकार के पास गोदाम ही नहीं कि वह प्रोक्योर किया हुआ अनाज रख सके। लेकिन इसके बावजूद अगर प्राइस राइज हो तो यह अत्यन्त ही चिन्ताजनक बात है। प्रोक्योरमेन्ट भी अच्छा हो रहा है, उत्पादन भी अच्छा हो रहा है और उसके साथ ही प्राइस राइज भी अच्छा हो रहा है--इसका तुक नहीं बैठता। यह अत्यन्त गम्भीर स्थिति है।

इसके साथ एक और विचित्र बात सामने आई है। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका अनाज का इनटेक घट गया है जैसे 83 में 16.21 मिलियन टन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए दिया गया था तो 84 में मात्र 13.47 मिलियन टन ही हुआ, यानी 3 मिलियन टन घट गया। इससे दो-तीन बातों पर चिन्ता जनक ढंग से विचार करने के लिए हम मजबूर होते हैं।

[उप सभापति महोदया पीठासीन हुई।]

ऐसा लगता है कि जनता की परचेजिंग पावर घट गई जिससे वह चीजों को खरीद ही नहीं पाती। यह अत्यन्त चिन्ताजनक स्थिति है। इसी के चलते प्रधान मंत्री या सरकार ने घोषणा की है कि हम आदिवासियों के लिए सस्ती दर पर गल्ला देना शुरू करेंगे। यह अच्छी बात है कि आदिवासियों के लिए दिया जाए, लेकिन जो अत्यन्त दरिद्र समुदाय है वह सिर्फ आदिवासियों का ही नहीं है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा दिए जाने वाले गल्ले में जो तीन मिलियन टन घट गया है यह आदिवासी-गैर आदिवासी दोनों के लिए हुआ है। इस लिए सभी गरीब समुदाय के लिए राशन का दाम घटाना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा मंत्री जी से कि हमारा जो कास्ट आफ लिविंग इन्डैक्स है वह मूल्यों की सही झलक नहीं देती। कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स सही माने में मूल्यों को रिकार्ड नहीं करता। पहली बात तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश के अन्दर एक बहुत बड़ा समुदाय है आबादी का जो अनकवर्ड है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, गैर सार्वजनिक वितरण वालों के लिए अलग से कोई कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स नहीं रखा जाता। शहरों में गरीबों का एक हिस्सा है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है। ग्रामीण समाज भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नहीं आता। गांवों में किरोसिन तेल की कीमत 7 रुपया लिटर है और चीनी की कीमत 8-10 रुपए किलो है। गांवों में दवाएं शहरों के मुकाबले 25 से 50 परसेन्ट ज्यादा कीमत पर बिक रही है। यही हालत दूसरे सामानों की है। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कवर्ड नहीं है व वोकल सेक्शन नहीं है। वोकल सेक्शन शहरों में रहता है। यहां बिजनेस क्लास के लोग हैं, पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, लेकिन गांव में जो अत्यन्त गरीब हैं, जिनका जीना कठिन है, उनके लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि वोकल सेक्शन के डर से सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात न सोचे, लेकिन जो यथार्थ स्थिति है उस पर विचार करे। इस सिलसिले में मैं मांग करता हूं कि जो अनकवर्ड सेक्शन है उसके लिए अलग कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स सरकार बनाए। तब ही असली बात का पता चलेगा कि उन लोगों की क्या हालत हो रही है।

सरकार की ओर से बार-बार कहा जाता रहा है कि अगर पैदावार बढ़ जाए तो चीजों की कीमतें कम हो जाएंगी। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि कोयले का उत्पादन बढ़ गया, कई करोड़ टन कोयले का दो साल से ज्यादा हुआ पिटहेड पर स्टाक जमा है, लेकिन कोयले का मूल्य घट नहीं रहा है। इससे यह बात जाहिर होती है कि वर्तमान पूंजीवादी

पद्धति में अगर पब्लिक सैक्टर भी उत्पादन कर दे तब भी चीजों के मूल्य प्रभावित नहीं होते । इसी तरह सूत का प्रोडक्शन पहले से ज्यादा हो गया लेकिन उसकी झलक कपड़े के मूल्य में नहीं आती । जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर फंड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा तब भी दाम बढ़ा । सरकार के पास जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी कहा और पहले से भी सरकार कहती रही है कि वह विदेशों से मांग लेती है । खाद्यान्न मंगाना तो अब समाप्त हो गया है और यह एक अच्छी बात है, लेकिन खाद्य तेल आप मंगा रहे हैं। चीनी मंगा रहे हैं हालत यह हो गयी है कि अब तो सिक्के भी हम विदेशों से मंगवाने लगे हैं पता नहीं प्राइस राइज रोकने के लिए अगर कोई ऐसी उच्च तकनीकी की मशीन मंत्री महोदय को अमरीका में मिल जाए कि जिस से प्राइस राइज रुक जाती हो तो वे उस को भी मंगा लें । ऐसा होने पर ही कोई मूल्य वृद्धि रोकने का रास्ता नजर आता है नहीं तो कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता । यह मैं इस लिए कह रहा हूं कि हम लोग आजादी की लड़ाई के युग में, गांधी जी के युग में राजनीति में आए और उन्होंने सिखाया था कि विदेशी माल का बायकाट करो । पुराने गांधी ने कहा था कि विदेशी माल का बायकाट करो और हमारे नए गांधी कहते हैं कि हर चीज विदेश से भारत में ले आओ । यह बात चिन्ताजनक है और इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर रोक लगनी चाहिए । आज आप देखिए कि दवा की कीमत क्या है ? बाजारों में लाइफ सेविंग मल्टी नेशनल कंपनीज के जरिए उनको गायब कर दी जाती हैं और यह सब किया जाता है । मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा और सदन को जानना चाहिए कि बहुत सी दवाइयां आज ऐसी हैं कि जिन का मूल्य भारत में अमरीका की अपेक्षा, इंग्लैंड की अपेक्षा या योरप के अन्य देशों की अपेक्षा ज्यादा है । यह आप कौन सी हाई टेक्नालोजी विदेश से मंगा रहे हैं जिस से हम को दवाइयों का मूल्य ज्यादा देना पड़ रहा है ।

अभी जो नई टेक्सटाइल नीति की गयी उस के बाद से कपड़े की कीमत में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है । कहीं-कहीं तो 25 परसेन्ट से ज्यादा और 50 हुई है । सरकार ने कहा था कि यह कपड़े की नयी नीति निर्धारित करने परसेन्ट तक के बीच में कपड़े में वृद्धि के बाद कपड़े का जो घरेलू उद्योग है उस को बढ़ावा मिलेगा । लेकिन हम हैं कि जो हैंडलूम वाले हैं उन को आज उचित मूल्य पर सूत नहीं मिल पाता है । पहले से ज्यादा कीमत पर उन को सूत मिलता है और इसी लिए बाजार में हर तरह के कपड़े के दाम बढ़ गए हैं । इस से स्पष्ट लगता है कि मूल वृद्धि का कारण सरकार की नीति है । मंत्री महोदय ने कहा कि अभी उनको चीनी के दाम बढ़ा देने पड़े । पता नहीं क्यों दाम बढ़ाना पड़ा । क्या विदेशों से वह चीनी मंगाते हैं इस लिए दाम बढाना पड़ा? विदेशी चीनी तो आप खरीदते हैं दो रुपए किलो का कीमत पर उसके चलते दाम कैसे बढ़ाना पड़ेगा । उस के चलते तो आप को दाम घटाना पड़ सकता है । सरकार को इस का जवाब देना चाहिए कि आप क्यों चीनी का दाम बढ़ा रहे हैं । आप क्यों वनस्पति का दाम बढा रहे हैं ? जब सरकार ही दाम बढ़ायेगी तो मूल्य-वृद्धि तो होने वाली ही है । मैं समझता हूं कि सरकार की नीति के चलते चीजों की कीमतें बढ़ती हैं । उन्होंने इस के एर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर के जरिए कोयले के, लोहे के, इस्पात के, सीमेन्ट के, हर चीज के दाम बढ़ा दिए और जिस का परिणाम यह हो रहा है कि तमाम चीजों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं—और इसी लिए यह कहना सही होगा कि इस की जिम्मेदारी खुद सरकार पर है जिस के चलते ऐसी स्थिति देश में पैदा हो गयी है ।

मैं एक और विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । अभी जो चीनी की स्थिति हो गई है उस के लिए

[श्री चतुरानन मिश्र]

पूर्णतया सरकार ही जिम्मेदार है । सदन को याद होगा कि तीन साल पहले जब ईख की कीमत बढ़ायी गयी थी तो भारत में इतनी चीनी पैदा हुई थी कि जितनी विश्व में किसी देश में नहीं हुई थी । न सिर्फ हम सेल्फ सफीशियेन्ट हो गए थे बल्कि हम ऐसी स्थिति में आ गए थे कि हम चीनी का निर्यात करने लगे थे । लेकिन सरकार ने ऐसी नीति से काम लिया कि हम को फिर चीनी विदेशों से मंगानी पड़ रही है । यह कितनी लज्जाजनक बात है कि कोई देश जो कृषि प्रधान हो, जहां हम चीनी का निर्यात किया करते थे वहां हम को विदेशों से चीनी मंगानी पड़ रही है। कारखाना मालिकों के हक में कहना चाहता हूं कि इस के पीछे आप को किसानों के द्वारा उपजायी गयी चीजों की उन को उचित मूल्य न देने की नीति है। फिर किसान मार खा जाते हैं और इस के चलते उत्पादन में कमी हो जाती है । अभी आप ने होल सेल प्राइसेज के कुछ नीचे जाने की और कुछ चर्चा की, लेकिन मैं आप का ध्यान दिलाऊंगा कि अभी नारियल के मार्केट में जो मन्दी आयी है उस के चलते नारियल के तेल के दाम घट गए हैं । वह भी इन के बसका एक आइटम है । ऐसी हालत में किसान असहाय हो जाते हैं । जूट इस साल बहुत ज्यादा पैदा हुआ । पिछले साल जूट का दाम इतना बढ़ गया था कि भारी संकट पैदा हो गया था । किसानों ने जूट ज्यादा पैदा किया तो इस साल संकट आ गया और कीमत घट गई । तो आपका नारा था कि हम ज्यादा उत्पादन करें तो उन्नति करें, लेकिन हो क्या रहा है कि प्रोड्यूस एण्ड पैरिश । अगर ज्यादा उत्पादन करोगे तो तुम्हारी बरबादी होगी । जूट के किसान, नारियल के किसान बरबाद हो रहे हैं उसके साथ ही रुई उत्पादन करने वाले किसान भी बरबाद हो रहे हैं । तो आपकी कोई मूल्य नीति नहीं है । आपने निर्धारित किया कि हम मार्केट फोर्सेज पर उनको छोड़ देते हैं फिर यही डिमांड एण्ड सप्लाई का सिद्धान्त आ जाता है डिमांड एण्ड सप्लाई किताबों में पढ़ने पर सिद्धान्त में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जिस देश को एकाधिकारियों और पूंजीपतियों तथा होलसेलरों ने बांट लिया हो, वहां यह नियम लागू नहीं हो सकता । यह मार्केट फोर्सेज पर छोड़ देने का मतलब है कि भारत की जनता को शेर के, भेड़िए के हवाले कर देना । उसी का परिणाम है कि देश में चीजों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ती जा रही हैं । सरकार इनको रोकने में बिलकुल असमर्थ रही है ।

उपाध्यक्ष महोदया, एक बात सरकार की ओर से बार बार कही जाती है कि कम्पिटिशन अगर हो जाता है व्यापारियों के अन्दर तो आप ही आप सही मूल्य हो जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा भारत के थोक व्यापारियों और एकाधिकारियों एवं मल्टी–नेशनल कम्पनियों ने इस देश का आपस में बटवारा कर लिया है और उस प्रभुत्व पूर्ण, बंटवारे के जरिए माल की वे आर्टीफिशिअल स्केयरसिटी पैदा करते हैं जिसके चलते चीजों की कीमतों में इतनी वृद्धि होती जा रही है । मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं । पुराने जमाने में एक राजा बहुत अफीम खाया करता था और अफीम खाने के बाद वह चार पैसे का मक्खन भी खाता था । जिस नौकर को उसने मक्खन लाने के लिए रखा था वह चार पैसे का मक्खन लाने के बजाए तीन पैसे का लाता था और एक पैसा खुद खा जाता था । राजा ने सोचा कि एक और नौकर रख लिया जाए तो इसकी चोरी बन्द हो जाएगी । उसने दूसरा नौकर रख लिया । दूसरे व पहले नौकर ने मिलकर दो पैसे खाने शुरू कर दिए और राजा के लिए 2 पैसे का ही मक्खन आने लगा । राजा ने उनकी चोरी रोकने के लिए तीसरा नौकर रख लिया । तीनों ने मिलकर एक-एक पैसा खा लिया और केवल एक पैसे का मक्खन आने लगा । राजा ने उन तीनों की चोरी बन्द करने के लिए चौथा नौकर भी रख लिया । अब चारों नौकरों ने मिलकर चार पैसे खा लिया और एक दुकानदार के पास गए कि मक्खन का सेम्पल दिखाओ राजा के लिए मक्खन खरीदना है । उस सैम्पल के मक्खन को लाकर राजा के सबसे पुराने

नौकर ने रात को जब राजा अफीम खाकर सो चुका था, उसकी गाल में लगा दिया। राजा सवेरे उठकर नौकरों पर नाराज हुआ कि वे रात को मक्खन क्यों नहीं लाए तो सबसे पुराने नौकर ने कहा कि हुजूर आप मक्खन खा भी गए हैं और नाराज भी हो रहे हैं। उसने राजा की गाल पर लगा हुआ मक्खन दिखाया। तो यह तो पुराने राजाओं का हाल था। अब तो नए राजा वित्त विभाग को सम्भाल रहे हैं, मैं उसे कहूंगा कि चोर बाजारियों पर आप भरोसा मत कीजिए। ये आपके गाल में मक्खन लगा रहे हैं, सारा पैसा खा रहे हैं और हमको बदनाम कर रहे हैं। इसलिए यह कम्पिटिशन की बात चलने वाली नहीं है। कागज पत्र से आप इनको नहीं पकड़ सकते क्योंकि वे उचन्ती खाते रखते हैं। केसरी जी से पूछिए ये उचन्ती खाते का हिसाब बता देंगे, उनको इसका विशेष ज्ञान है। वे जानते हैं कि ये लोग कैसे करते हैं। इसलिए जो बात आप सोच रहे हैं वह चलने वाली नहीं है। क्या आप एक भी देश ऐसा बता सकते हैं जहां मार्केट फोर्सेज पर छोड़कर मूल्य नियन्त्रण किया गया हो? क्या एक भी देश बता सकते हैं जहां पूंजीवादी तरीके से मूल्य निर्धारित हुए हैं? बेरोजगारी रुकी है। ऐसा तो कहीं भी नहीं है। अमरीका में बड़ी तेजी से मूल्य वृद्धि है, जापान में मूल्य वृद्धि है। जर्मनी में मूल्य वृद्धि है। इंगलैंड की बात तो छोड़ दीजिए वहां तो बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि और भी ज्यादा है। इसलिए यह तरीका चलने वाला नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जो आपने नई नीति निर्धारित की है वह अत्यन्त ही खतरनाक है इसको आप रोकिए। जो थोक व्यापार है उसको आप अपने हाथ में लीजिए और जो एक्स मिल प्राइस है उसमें सामान लेकर लोगों में उसका वितरण कीजिए। किसान को उचित मूल्य दीजिए ताकि उनको इन्सेंटिव हो ताकि वह अच्छी खेती कर सके। जैसा गन्ने का करके देखा है, गल्ले का करके देखा है, नारियल का करके देखा है, जैसा जूट का किया, आपकी इस नीति के चलते यह सारा देश बर्बाद हो रहा है। इससे एक और घातक परिणाम है जो चिन्ता का विषय है। वह घातक परिणाम यह है कि पिछले 5 वर्षों से हमारा विदेश व्यापार बहुत बड़े घाटे में चल रहा है। 5-6 हजार करोड़ रुपया सालाना घाटा हमारा विदेश व्यापार में जा रहा है तो ऐसी स्थिति में अपने देश को सेल्फ सफिशियन्ट करने का आपका नारा प्रमुख नारा होना चाहिए। सरकार ने यह नारा दिया है कि हम इम्पोर्ट करेंगे, जैसा मैंने आप से कहा हर चीज के इम्पोर्ट करने के लिए सरकार कहती है। अभी उसमें भी एक खतरनाक बातें है। खतरनाक बातें वैसी पहले भी हुई थी जब कामनवेल्थ की बैठक में हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि साउथ अफ्रीका का आर्थिक बायकाट किया जाए तो अमरीका ने धमकी दी थी अगर साउथ अफ्रीका का बायकाट करेंगे तो अमरीका बायकाट करने वालों का बायकाट करेगा। एक नई धमकी फिर आई है वह यह है कि अमेरिका ने कहा है या तो नया गाट कान्फरेन्स, जनरल एग्रीमेंट आन ट्रेड एण्ड टैरिफ दूसरी गाट कान्फ्रेंस बुलाई जाए जिसमें मान लें कि सर्विस भी व्यापार है सर्विसेज का अर्थ यह किया है कि बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, ट्रांसपोर्ट, एयर सर्विस, इन सारी चीजों को आप व्यापार के अन्दर ले आइए। अगर आप इसको नहीं लाते हैं तो हम आपको जनरल प्रिफेन्शियल व्यापार की जो सूची है उस सूची से आपका नाम काट दिया जायेगा। यह अत्यन्त ही अपमानजनक धमकी अमेरिकन सरकार की ओर से मिली है। मैं यह चाहूंगा कि इस धमकी का सरकार जवाब दे। मैं चाहता था कि स्पेशल मेंशन के जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित करूं लेकिन वह अभी तक लम्बित है। मैं चाहूंगा कि जब दुनियां का एक सबसे बड़ा साम्राज्यवादी देश खुले आम हम को धमकी दे रहा है कि हम आपको उस सूची में से निकाल देंगे वैसी हालत में सरकार अगर बेहिसाब इम्पोर्ट की नीति का ही अनुसरण करती है, अपने किसानों को तरजीह देने की नीति नहीं अख्तियार करती है, चोरबाजारी को तरजीह देती है और पूरे समाज को भेड़ियों के हवाले करती

[श्री चतुराजन मिश्र]

है, तो यह देश, मैं कहना चाहता हूं, अत्यन्त खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएगा और इसके अत्यन्त खतरनाक परिणाम होंगे। अमेरिका, अपना जो उसका व्यापार का घाटा है, डेढ़ सौ मिलियन डालर से ज्यादा का सलाना घाटा उसकी पूर्ति के लिए हम लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। मैं चाहूंगा कि ऐसी नीति का हम अवलम्बन करें जिससे हम अपने देश को सेल्फ सफिशियंट बनाएं। लेकिन पिछले कुछ दिनों के अन्दर जिस नीति का आपने अवलम्बन किया है उससे यह सारा देश दिवालियापन की ओर जा रहा है और सारी जनता अत्यन्त संकट में है। इसलिए मैं फिर दोहराता हूं इस बात को कि दो तरह का कास्ट आफ लींविंग इंडेक्स रखा जाए, एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाले हैं और दूसरे गैर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वालों का गरीब किसानों के लिए। तब पता चलेगा कि असल स्थिति क्या है? जब जन साधारण के लिए एक एक रुपए का मूल्य घट कर 13 पैसे पर चला गया तो मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि आप इस बात की जांच करें कि उन गरीबों के लिए जो दरिद्रता की रेखा के नीचे रहने वाले हैं उनकी क्या हालत है। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से फिर आग्रह करूंगा कि अपना इस नीति का घातक नीति को देश के लिए डुबाने वाली नीति का परित्याग करें और जन साधारण को राहत दिलाए। होल्सेल ट्रेड को अपने हाथ में ले, एक्स मिल प्राइज पर चीजों को अपने हाथ में ले और उसका उचित वितरण करें लोगों तक पहुंचाएं, किसानों को उचित दाम मिलें ताकि उत्पादन बढ़ा सकें। इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव आपके सामने रखता हूं।

SHRIMATI KANAK MUKHERJEE " (West Bengal): Madam, while discussing the problem of price rise, I remember the famous lines of S.T. Coleridge in Ancient Mariner: "Water water everywhere not a drop to drink." Such a cursed paradjxlcal situation of scarcity amidst plenty has been created in our country by the economic policies of the Union Gov- ' ernment. Madam we have had two decades of Green Revolution and two successive bumper harvest years, though we could not fulfil the Sixth Plan targets. We have a stockpile of foodgrains with the FCI. It has already reached 30 milloin tonnes and could even reach 38 or 39 million ton. nes. But we are burden with this excess stock. The Government granaries are overfull and the Government does not know what to do with it, as the people have no purchasing power to buy it. So they go hungry. Some 300 million people go starved or underfed. Such is the paradoxical situation which the Government has created. Now with this huge stock of food, the Government does not know what to do and they are even trying to export foodstuffs to get rid of this huge stockpile. Utilisation of the foodgrtins available can be made by introducing *a* massive programme of rural employment. Formerly it *1* was known as the Food for Work Programme; now it is called NREP. This can be easily utilised in that. It can directly give food to the people and it can build national assets. It can lead to an enormous growth of human

Capital and it can create innumerable manaays of employment. The | Government can even plan a com-prenensive midday meal scneiiie. to UK cnuaren. Thai way also this s.oekpi.e of loodgrains can be utilised. But the GOV ernmeut will not do it. It will keep pre-ponderant sections of the people. the major sections ot the nation's population excluded from the growth process. Thai t is way we could not make any spectacular economic growth. if the peopie are not involved, it we do not take into consideration ine prooiems of the majority of the popu.iauon, no Aryabhata or satellite or new technology will help the nation to i grow. Now the main thing is the income or the purchasing power of the nation's miajoiity. increasing their purchasing power is . the main thing, .out our economic policies, espe- I cialiy the new economic policies of the Government are ideologically reoriented to wards the direction of the Western capitalist countries and that also without land feroms and without fighting against the feudal legacies of our country. Now. see the rate of growth. The per capita income in our country is the least even among the developing countries. The per capita consumption of food and textiles has declined over these there-and-hall decades of independence of our country. Again due to the recent shift in the economic policies of the Union Government, the exports are sluggish and the imports have been liberalised like anything. We had never seen such a rise in imports , before. And in spite of the record foreign trade deficit, the prices of some goods are only marginally less than in the previous year. The retail prices aw riing faster .and faster than the wholesale prices. Now the rise in the wholesale prices also is over 300 per cent in the last one decade. In 1972 it was 200. Now it is over 600, Look at these price of sugar, the price of oil, the prices of ' all essential commodities. Here are the i'sto aid charts submitted by. the Government itself in Parliament, in the Rajya sabha and in the Lok Sabha. At least ten charts are with me showing a grad-mi rise in the prices of all essential commodities. Our honourable rriend has already mentioned about it. See how the Gov-ernment is favouring the sugar and oil lo-ouies. the ratio ot the levy sugar and the open market sugar was 65:35, Now they have changed the ratio to 55; 45. They have increased the price of levy sugar to Rs. 4.80 and consequently the price of the open market sugar has gone up to Rs. 7.80. In Delhi market sugar has been priced at Rs. 7.80, Look at the steep rise in the price of vanaspati. My friend has already mentioned it. From Rs. 244.50 vanaspati has risen to Rs. 265 or 15 kgs. That also has gone to the black market. So is the case with edible oil. Industrial quota has been reduced to 10 per cent and the pi ice of the imported oil is becoming very high. Oil looby and sugar loboy are the most favourable ones with the Union Government. the prices of all essential commodities like rice, oil, sugar, coal, kerosene, railway fares, steel, have been rising gradually and regularly. In contrast, the prices of agricultural products are falling. The poor peasants are suffering. The prices of jute, cotton, sugarcane, coconut, tobacco, are falling. This is the contradiction. The purchasing power of the people is becoming less and less. The purchasing power of the people is becoming less and lessand the price is lowering the real wages along with the growing unemployment creating the worst kind of economic situatoin for the common peopie.

Now look at the import-export pol'cy. While there is a steep rise in the prices of essential commodities, the prices of some other commodities are getting lesser and lesser. What are those commodities? Luxury good like TV, coucolu T.V. re-frigerator and some electronic goods, which are used ony by 5 psr cent of the people of our country. So I ask th»se categorical question: Is the Union Governmsnt going to take extemiv? stens for creating work on"0-rtunities, as, for example, under the NR-EP, for utlising the huge food stocks an<f at the same time for developing the nation and national assets? Secondly [- ♦h-Government going to revise its import-

[Shrimati Kanak Mukherjee]

export policy so that the country may become self-reliant and the people may be relieved from the rigours of the existing economic situation? What steps is the Government going to take to supply essential commodities to the people at fair prices? The West Bengal Government has been suggesting for years, let the Union Government take up the responsibility of supplying at least fourteen essential commodities to the common people all over India at fair prices, but the Union Government is not taking any action towards that end. Will the Government think about the suggestion of the West Bengal Government and take necessary steps in that direction? Next: Is the Government going to revise its policy of indirect taxes, its policy of decreasing the prices of luxury goods and increasing the prices of essential commodities? Lastly, will the Government abide by the democratic opinion of the people and Parliament and stop taking administrative decisions concerning price rise and essential commodities at its own sweet will? These are my categorical questions to the Union Government. Thank you.

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (हरियाणा): मैडम डिप्टी चेयरमैन, महंगाई का मसला बहुत अहम है और अभी हमारे सामने मिश्रा साहब ने और बहन मुखर्जी ने अपने विचार रखे हैं। महंगाई के लिए जो यह होल सेल प्राइस इन्डेक्स है यह पुराने हिसाब से चालू है और इसी के आधार पर सरकार का जवाब है।

हमारे सामने यह स्टेटमेन्ट जो है उसके अन्दर आंकड़े जो हैं बराबर यही दिखाए हैं कि होल सेल प्राइस इन्डेक्स जो है उसके अन्दर कमी होती जा रही है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है। हमारे यहां व्यापारी कहते हैं कि लेखा ज्यों का त्यों और कुनबा डूबा क्यों। मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि प्राइस इन्डेक्स गिरता जा रहा है लेकिन बाहर महंगाई कैसे बढ़ती जा रही है। क्या इस बात की, जवाब की, जांच करने की कोशिश करेंगे, यह तकलीफ गवारा फरमायेंगे मंत्री महोदय, यह तो एक रूटीन मसला बन गया है इस मसले के ऊपर बहस मुबाहिसा करने का, कौन सा सेशन ऐसा है जिसके अन्दर महंगाई की बाबत सारा हाउस इसको डिसकस नहीं करता। पिछले सेशन में भी बहस हुई थी और आज इस सेशन के अन्दर भी। क्यों? क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ कारखानेदारों को रियायतें दी गयी हैं जैसे वनस्पति और शूगर के जो मैग्नेट्स हैं उनको भी इसी तरह से रियायतें दी गयी हैं। मैं यही एक अर्ज करना चाहता हूं कि अब जैसे हम इसके ऊपर बहस कर रहे हैं, हाउस के अन्दर महंगाई के मसले के ऊपर तो बाहर महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन यहां मिनिस्टर साहब हमें इंडेक्स के अन्दर दिखाकर यह बताते हैं कि होलसेल प्राइस इन्डेक्स में कमी हो रही है, हालांकि बाहर महंगाई है। यहां जैसे हम बोल रहे हैं लेकिन बाहर महंगाई बढ़ती जा रही है इसका कारण क्या है? क्या कभी हमारी सरकार ने इसकी गहराई तक जाने की कोशिश की है? जिक्र किया जाता है कि फलानी चीज की कीमतों के अन्दर रियायतें दी गयी हैं यह एफलुएंट सोसाइटी के लिए जो टेलीविजन वगैरह चीजें इस्तेमाल करते हैं, होता है लेकिन गरीब आदमी का गरीब किसान का और मजदूर का जो देहात का रहने वाला है उसका क्या हाल है। हर एक चीज जो वह पैदा करता है पैदा करके बाजार के अन्दर बेचता है फिर कोई चीज खरीदने के लिए जाता है तो होता यह है कि उसकी चीज बाजार में सस्ती हो जाती है और जब वह जरूरियात की चीजें बाजार के अन्दर लेने के लिए जाता है तो हर एक चीज उसको महंगी लेनी पड़ती है। हमारे देश के अन्दर सब पैदा होता है, और हमारे देश में ही, लोहा यहां पैदा होता है। आप हर एक चीजों की कीमतें देखें और फिर जापान से कम्पैरीजन करें इन सारी चीजों की यानी हमारे देश के अन्दर जो चीजें हैं उनको उन्हें इम्पोर्ट करना पड़ता है इसके बावजूद भी उनके यहा कीमतें कम हैं और हमारे देश के आन्दर ज्यादा है। मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि कोई एक पार्लियामेन्ट की कमेटी

या हाई-पावर्ड कमेटी इस चीज के अन्दर मुकर्रर करने की कोशिश करें जो इस सवाल के अन्दर जाये । पब्लिक सेक्टर कम्पनीज जो ओवर हेड एक्सपेन्सेज बढ़ा कर चीजों की कीमतें बढ़ाती हैं उसको वह देखें कि क्या वास्तव में है ? वरना यह ब्यूरोक्रेसी कभी कीमतें कम नहीं आने देगी, इसने बुरी हालत कर दी है । मैं फाजिल मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर सब चीजें, हर एक चीज महंगी है और अगर कोई चीज सस्ती है तो गरीब की आंख का आंसू सस्ती है या इस देश के अन्दर मौत सस्ती है । भूखे मरो, भूखे रहो, मर जाओ, मौत बड़ी जल्दी आराम से मिल जायेगी । यहां भूख से गरीब की आंख के अन्दर आंसू मिटने में नहीं आता है । मेरी समझ में बात नहीं आती कि गरीबी-हमें किसी की तरफ बर्डन शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है । बाजे दफा यहां पर बहस भी की जाती है, आपोजीशन वाले जिक्र करते हैं और हमारे मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जनता गवर्नमेंन्ट के अन्दर क्या था, क्या जनता गवर्नमेन्ट करती थी ?

How are we concerned with the Janata Government? We are concerned with what we are people.

जिनकी हम राय लेकर यहां नुमांदगी करने के लिए आते हैं । यानी इस मंहगाई ने आज गरीब किसान और मजदूर के जिस्म के अन्दर, उसकी छाती के अन्दर छेद किए हुए हैं, उसके जिस्म पर फोड़े बने हुए हैं, पर वह बोल नहीं सकता क्योंकि उन फोड़ों के न मुंह है, न जुबान है, वाह बोल नहीं सकता ।

How long are we going to feed all these on empty slogans?

जो कहते हैं, मैडम, कि –

> मरजे इश्क पर रहमत खुदा की,
> मरज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की ।

मैंने आपसे अभी जैसे अर्ज किया था कि जितनी इसके ऊपर बहस करते हैं, उतनी मंहगाई बढ़ती जाती है, यानी वही चीज होती जाती है ।

तो इसको कम करने के लिए–और यहीं नहीं, मैडम, यह मंहगाई उस गरीब को ही नहीं, यह तो इस हाउस के अन्दर हमें भी सता रही है, और आप देखिए कौनसी चीज हमें सस्ती मिलती है और छह महीने हो गए, मेम्बर्ज यहां कहते हुए शर्मिन्दा हैं, पर बाहर कहते हैं कि हमारी दाल, पानी, रोटी का भी बिल कभी आएगा कि नहीं क्लियर हो चुका पर अभी नहीं आया ।

अब हमारा बिजली का बिल अढ़ाई–तीन सौ रुपए आता था, पर आज आठ–नौ सौ रुपये आते हैं । मैंने खुद चिट्ठी लिखी है कि यह इतना 1200 रुपए का बिल कैसे आ गया जब कि पहले अढ़ाई–तीन सौ रुपए का ही बिल आता था। मेरे तो सारे, टोटल इमाल्यूमेंन्ट्स इतने नहीं हैं ।

I am not going to pay

और यहां पर मिलता क्या है? यहां से 550 550 से 700 रुपए तन्ख्वाह है, सो कहां से बिल दें । आज कौनसी चीज है जो सस्ती मिलती है। कहने लगे कि बिजली की दर एन.डी.एम.सी. ने बढ़ा दिए हैं । तो उन्होंने बढ़ा दिए, पानी के दाम भी बढ़ा दिए उन्होंने, कार का पेट्रोल भी बढ़ गया । कार तो मिलना मुश्किल है, जीप लेना मुश्किल है । सरकार और यह हमारी पार्टी वाले हमें कहते हैं कि जाओ कांस्टीट्यूएंसी में, पर वहां कैसे चले जाएं, किस चीज के ऊपर चले जाएं ? करें क्या ? छह महीने हमें हो गए इस चीज का इन्तजार करते हुए––एक चीज तो है नहीं । गरीबी तो सब किसी को तंग करती है, और मैं तो कहता हूं कि जो आदमी यहां पर साईड बिजनेस करते हैं या जिन-जिन के कारखाने चलते हैं, वही कर सकते हैं, हमारे जैसा गरीब आदमी जो जमींदार है, जिसकी जमीन भी सारी एक्वायर हो चुकी है, दो–तीन एकड़ छोड़ी है बड़ी मुश्किल से गवर्नमेन्ट ने और हम उसके सहारे के ऊपर बैठे हुए हैं । तो कैसे हमारा काम चलेगा, मेरी समझ में बात नहीं आती ।

मैं तो अपने आनरेबल मिनिस्टर से यही गुजारिश करूंगा कि इन सारी चीजों के अन्दर जाएं और सौतेली मां जैसा सुलूक वह

[श्री मुख्तियार सिंह मलिक]

किसान के साथ, गरीब मजदूर के साथ नहीं करें।

आज देश की मण्डियों के अन्दर क्या हालत हो रही है? हरियाणा की मण्डी के अन्दर जाकर देखें, पंजाब की मण्डी के अन्दर जाकर देखें। हम महीनों तक रोते रहे कि कितनी बुरी हालत है कि देश के अन्दर चावल पैदा नहीं होता, गेहूं नहीं होती। आज पैदा किया, तो उसकी हालत क्या है?

आप अखबारों के अन्दर पढ़ते होंगे कि पंजाब के अन्दर आज लाखों टन चावल खराब हो चुका है, क्योंकि एफ.सी.आई. ने उठाया नहीं। हमने अपने चीफ मिनिस्टर के पास जाकर कहा कि हमारी मण्डियों के अन्दर क्या हो रहा है, एफ.सी.आई. एन्टर नहीं होती, किसान की जिन्स को खरीदती नही और उधर किसान मरता जा रहा है और उधर वहां मण्डियों के अन्दर ग्लट हो गया है इस पर चीफ मिनिस्टर ने फाजिल मिनिस्टर को टेलीफोन किया कि किसी तरह इसका कुछ करने की कोशिश करो और उन्होंने अपनी एजेन्सी नैफेड और फूड सिविल सपलाईज डिपाटमेन्ट को कहा कि कुछ तुम खरीदो, लेकिन एफ.सी.आई. एन्टर नहीं हुई। कितनी लेट स्टेज पर, यानी कब सीजन शुरु किसानों की जिन्स की है। मण्डियों के अन्दर भी उन्हें परेशान पड़ता है। वहा उन्हें रिफ्यूज किया जाता है। कहा ज्यादा नमी है और वेट मशीन दिखा देते हैं उसे अन्दर लटका करके, 22 परसेन्ट पहुंच गया 25 परसेन्ट पहुंच गया हम इसको लेने के लिए तैयार नहीं। यह हम मानते हैं कि एक-दो दिन के अन्दर फर्क पड़ जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसी ढेरी को मण्डियों के अन्दर व्यापारी लोग ले लेते हैं और अगले ही दिन वह बिक जाता है। 126 रुपए के हिसाब से। 16 रुपए एक रात के अन्दर मुनाफाखोर मुनाफा कमाते हैं। सरकार ने उसके लिए क्या किया। मैं बड़ी तवक्के रखता हूं आनरेबल मिनिस्टर साहब से, ही इज बैरी यंग। यह तो बड़े एड-मिनिस्टर रहे हैं इनकी पीछे की हिस्ट्री रही है, इनके डिपार्टमेन्ट सम्भालने के बाद हमें बड़ी भारी तवक्के थी कि थिंगज विल इम्प्रूव। मैं यह समझता हूं कि किसान और मजदूर को देने के लिए कुछ करने की हम कोशिश करें। इसके अन्दर यह बात नहीं है कि हमारी पार्टी वाले या हमारी गवर्नमेन्ट, क्योंकि हमारी पार्टी की गवर्नमेंट है, हमारे आनरेबल मिनिस्टर हमारी बात का बुरा नहीं मनायेंगे, क्योंकि जो हालत इस समय चल रही है हम तो उसे कह रहे हैं वायूट डिफैंड रांग थिंगज एण्ड रांग पालिसीज एट आल। जो चीजें वहां पर चल रही हैं वहीं बात हम कह रहे हैं। अगर ये सब चीजें हम यहां पर नहीं कहेंगे तो ये चीजें उनके नोटिस में कैसे आयेगी। रोजाना जो स्टेटमेन्ट आते हैं उस हिसाब से आंकड़े लेकर जायेंगे तो क्या दुकानदार उस हिसाब से सस्ती चीज दे देगा? होल सेल प्राइस इंडेक्स गिरता है तो क्या उसका कीमतों पर कुछ फर्क पड़ता है? सुगर के दाम बढ़े हैं, जैसे तिल का तेल पैसे कम बढ़ा देते हैं। कभी सुगर की कीमत कम आयेगी तो क्या चाय के कप की कीमत कम करने को कोई तैयार होगा? आज वनस्पति के दाम बढ़ गए तो उसके साथ-साथ सभी तेलों के दाम बढ़ जाए तो चाय वाले दस हैं, सरसों का तेल है, फलां चीज है, सभी चीजों के दाम बढ़े हैं। यही नहीं आज सारा हिन्दुस्तान क्या गैस का प्रयोग ही जलाने के लिए करता है? हार्ड कोक चाहिए, साफ्ट कोक चाहिए, विच इज नाट एवेलेबल इन दी मार्किट, वह मार्किट में नहीं मिलता है। वह ब्लैक के अन्दर मिलता है। हमें भी बार-बार पैट्रोलियम मिनिस्टर को लिखना पड़ता है। तीन-तीन दिन तक हमें गैस का सिलैन्डर नहीं दिया जाता। बीस रुपए ब्लैक में गैस का सिलेंडर मिलता है। कई बार पुलिस को भी सूचित करके देख लिया है। प्राइज चीजों के लिखो हुए हैं, लेकिन इसका नोटिस लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। पीछे तो सिगरेट की डिब्बी

के एक-एक पैकेट के तीन-तीन चार-चार रुपए ज्यादा लिए हैं । क्या उसके लिए हम थाने में जाएं कि हमारे से इतने रुपए ज्यादा लिए हैं ? वहां जायेंगे तो उसमें भी घन्टे लगेंगे और पुलिस के रवैसे तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे । मेडम आप तो हाइली आफिस पर बैठी हुई हैं और हमारे जैसे साधारण आदमी तो पैदल फिरते हैं । हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है ।

उपसभापति: लेकिन बाजार तो हमें भी जाना पड़ता है ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक: लेकिन आपका तो वास्ता बाजार में जाने का ज्यादा नहीं पड़ता । हम तो साधारण आदमी हैं हमें तो सारी चीजें स्वयं खरीदनी पड़ती हैं । अभी मिनिस्टर साहब बता रहे थे हमें तो सारी चीजें स्वयं खरीदनी पड़ती हैं । हम तो साधारण आदमी हैं हमको तो ऐसा कुछ नहीं मिलता कि हम नौकर रख सकें । हम नौकर रखें तो किस चीज से रखें ? कनक्ल्यूड करते हुए मैं फाजिल मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि देश के अन्दर गरीब जनता की बहुत ही बुरी हालत है, उसको संवारने की कोशिश करिए । मंत्री जी ने आंकड़े देने की कोशिश की । उनको वे अपने पास ही रखें और अपने अफसरों को कहें कि मैं इनको सुनने के लिए तैयार नहीं हूं । अगर वह उनको कह देंगे कि आइ एम नाट प्रिपेयर्ड टू हियर द स्टेटिस्टक्स और प्रैक्टिस में क्या है, बाजार के अन्दर क्या भाव है, गरीब आदमी की किस तरह रंगाई और मंजाई की जाती है, इन सारी चीजों को देखकर ठीक करने की कोशिश करेंगे तभी स्थिति सुधरेगी । मैं उनका बहुत मशकूर हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr. Gurupadaswamy. Would the House like to adjourn for lunch at 1 PM or 1.30 PM?

SOME HON. MEMBERS: At 1 PM

THE DEPUTY CHAIRMAN: All right, you may speak now.

SHRI VISHV AJIT PRITHVIJIT SINGH (Maharasntra): Let him speaK lor live minutes now.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, he will continue later on.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY (Karnataka): Madam Deputy Chairman, this is a very important aeoate and this has come tor discussion after the meeting of the National Development Council which considered and finalised the Seventh Plan. And this has also come in the wake of various steps and measures fatten by the Prime Minister to contain inflation and contain the prices. And this has come nearly after seven or eight months after the Budget was passed. What is exactly the present situation* and what are the basic reasons for the present situation on the price front and on the economic front?

Madam, the statement of my hon. friend does not give the corn ct picture, I am afraid. He has played up certain facts and played down certain other facts. He has said that during the first seven months of the current financial year the wholesale price index has moved up by less than four per cent. And he has said at the end of that paragraph that the prices of some essential commodities have moved up, however. Here is the It is true that the wholesale price index has declined to a certain extent but he has not given us the reasons why this wholesale price index has declined somewhat. He has not given us which are the commodities which are showing decline in prices in recent months and which are showing the rise in prices. It is true that the prices of certain commodities have declined. This has been responsible for bringing down the wholesale price index to a certain extent.

We are really concerned here about the price rise in respect *oi* commodities of mass consumption. We are concerned with the rise in prices of

Shri M. S. Gurupadaswamy

essential goods which really touch the uuuget oi tne housewife.

1'UK DJSPUTY CHAIRMAN: Shall we continue aiter luncn.

The House is adourned tor lunch Ull Z OCiOCK.

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the ciock.

The xiouse reassemoxed alier luncn at tour minutes past two of the clock, lUe uepuiy 111.u1u1.tn in the Chair.

THE DEPUTY CHAiRMAN: We Shan continue with the discussion on tne piice situation. &hri uurupaaa-swamy to conanue his speecn.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Madam. I was saying in the pre-iuinh hour that the statement of my triend, the hon. Minister, is a camouflage and it tries to create a certain amount ot illusion that everything is line in the economic climate in the country, particularly in respect of prices prevailing at the present time. Madam, he has suppressed many things, as I said. He has not come out with the true state of things, the true state of affairs, the reality. He has given the wholesale price index. He has said, the price rise is not abnormal, it is contained, it is round about 4 per cent. Even 4 per cent rise is wrong. In a dangerous inflationary situation it is rather high. Apart from that, the house should take note of the fact that the price of essential commodities, articles of mass consumption, is rising. The Minister has said that there is availability of commodities but that is offset by escalation of prices. There has been a steep rise in wholesale prices of fruits and vege-tables, where the rise is near about 20.3 per r^nt. The price of eggs, fish and meat, Madam, has gone up nearly by 16.4 per cent. There has also been a steep rise in the wholesale price of sugar, khandsari, by about 19 per c[e]ht. The price of fuel and cereals also has risen by 10 per cent. There is a rise in price of motor vehicles and their parts by 15 per cent and 10 per cent. This wholesale price trend has been somewhat reduced by the decline in prices of certain other commodities. There has been a fall in the price of oilseeds, by 16.4 per cent. There is a fall in edible oil price mere or less to the same extent. There is a declined in price of a few items like jute, soaps cosmetics and the like. But the most important articles of mass consumption have been affected adversely as a result of this price increase.

My friend must be bloating over the fact that the price-affect has been contained, that the price-affect is somewhere near about 4 per cent but we cannot deal with this from limited angle. You have to look at the entire period since 1950-51. We have been having plan Development for more than 3 decades. Except in the first Plan, in all other Plans the rate of national income growth is somewhere near 3.5 per cent and the targeted rate was 5 per cent. The per capita income is round about 1.5 per cent, whereas the target was fixed at 2 per cent. Apart from this, if you go through the price rise throughout the period, you will see the enormity, of the situation, the alarming picture that is emerging. Except in 1951-56 Plan period, in all the other Plan periods there has been a continuance rise in prices of all commodities and if you take the base-year 1961-62 as 100 you will find only in the 1st Plan there has been a decline in price to the extent of 18 per cent. Then in 1965-66 the wholesale price increase is 131.6 per cent, in 1968-69 165.4 per cent in 1973-74 254.2 per cent in 1974-75 313 per cent, in 1975-76 313.3 per cent, 1976-77. 319.8 per cent and 1977-78 336.7 per cent. What the Indian economy suffered from in all these years. Madam, is this inflation price distor-tion, and these have, in a way affect-

ed our rate of growth, aflected the savings, the value, of savings, further this price increase has brougnt aoout distortions in distribution ox income and wealth in our society. Various aberrations have taken place as a result of tnis iniiation and price esca lation. ,

There is always a link between innauon and prices and giowtn. As a resuit 01 price uisioitioiis, erratic increase in prices in ail tuese years, tne pirfnnea aeveiopmeut nas saiiereu. rue oasic tilings ror tne common man nave not oeen aoie to be supp^ieu auequateiy. Keports are there that tne economy is not acnieving the targets ior all these years, except in the uirst Pian. Growth and stability we nave been talking about for long. Without stabilisation ol prices at a lower level, I am sure we will not be able to create the economic climate which is so necessary to bring about an adequate and sustained economic growth.

Madam, the Minister should take an overall view of the entire situation, price factor being the most important. What is being done is, the Finance Minister or the economic Ministries in the Government of India want to stabilise inflation at a particular level. They are not tackling inflation; they are stabilising prices at a high level which is not conducive for growth, which is not conducive for development and which will not meet the basic requirements of planning. So this attempt to stabilise inflation at a higher level is tfrong.

There has been no coordinated or integrated policy pursued by the Government in respect of price structure. I do not want to refer to cost in detail, but let me point out that when there is cost escalation, there has got to be steps taken immediately to adjust prices. There is such a time gap now between cost escalation and the adjustment of prices that it also has caused a lot of problem in respect of managing the economy. In other words there is no integrated approach to costs and prices in our country.

Madam, lastly, I would say that the Government has got to take immediate measures to see that the overall situation on the price front is tackled properly and adequately and efficiently. As the House is aware, 30 per cent of the wholesale price index consists of food articles. The rest of it consists of other manufactured articles. So, the wholesale price index will not give the entire story, the true story about the pricei that obtain in the market.

Years ago, I know, when I was in the House, Shri Lai Bahadur Shastri, the Prime Minister then, selected 14 commodities for fixing prices because he thought that by selecting those 14 commodities he would be able to contain the prices of those commodities which affected the common man and the house budget of many households. But that objective of Shastriji was was not implemented by the Planning Commission or by the Government. May I know ask my friend, the Minister, here to concentrate on essential articles of consumption and see that adequate provision is made, adequate machinery is provided, created, for the supply of these commodities to the needy, to the poor and to those who are below the poverty line and an effective machinery is created for that purpose? Merely saying that the wholesale price index is contained within 4 per cent or 5 per cent will not do.

As I said, in a potentially dangerous, inflationary situation iike ours, an inflationary trend of 4 per cent is equally dangerous. And we are planning for non-inflationary development What has happened to that? Even this 4 per cent with this accumulated, unprecedented, inflationary crisis will create havoc to our economy, will affect adversely the poorer section^ of our society and will create dlstor-

Shri M. S. Gurupadaswamy

tions and aberrations in our economic development, and it will destroy the value of savings, and it will 1 under-vaiue even the rate of growth. i

Therefore, Madam, may I appeal to tne Minister to have a realistic assessment of the price situation and bring aDOUt and worn out a proper strategy so that we' can nave price stability, we can have adequate supply and so tnat there -ntwy not be any cause lor distress in the economy.

SHfil RAMESHWAR THAKUR: (Bihar); Madam Deputy Chairman, tne ouoject wrucn is oeing discussed is vuaij ana naturally concern nas been expressed by iviemuers of trie House irom either side. It is necessary that we taice all such vital issues wnich concern the common man not on political grounds, not on party lines, out as national issues in which common people of the country are involved.

Madam, Shri Gurupadaswamy, in his speech, as a senior and seasoned parliamentarian, has raised the level of the discussion. However, certain as-: peels of the observations made by the hon. Member are full of political overtones or at least do not support the facts of the situation. Therefore, we can certainly deal with that matter in proper perspective. The Honourable Minister will certainly answer to the issues raised by the hon. Member. But I would like to share some of my thoughts on the basic issues raised by the hon. Member and some other Members in this House. The economic development issue has been raised by the hon. Member and he said that during the last 30 years we have not been able to achieve the desired economic goals fixed during the successive Five Year Plans. So far as the different plans are concerned, we are aware that our First Five Year Plan was started after the independence. Where was our economy after the Se? cond World War? Should we forget the fact tnat we were not havmg ade quate food stocks? Have we forgotten that lashs of people in West .bengal died for want for food? My hon. friend has pointed out mean achievement during the last 30 years- without g.v-ing any figures. But today by vir tue of tne policy pursued during the successive plans, the labour and the efforts of our farmers we are self-sufficient in foodgrains.' Not only that, we are in a position to export to other countries. Is it a fact that prices of essential commodities are higher? Is it a fact that production is less? I agree in some areas it is less. But we need to augment them. It is not a fact that we do not have sufH-cent stocks today. There is no psychological effect. There is no question of hoarding so far as food-grains are concerned or some other essential commodities are concerned. The production has to be further augmented in certain areas where we have to import certain essential com-modities to meet our requirements. But, nevertheless, we have today essential goods available in the market. The question may be of maldistribution or channel of distribution is de-fective. We are not able to reach the farthest corners of our vast country. There are areas where people face shortages of certain commodities which they would like to purchase apart from the fact of their purchasing power. Is it not a fact that in other areas also during the last 30 years—in the case of infrastructure, industrial development, science and technology, health services and educational facilities, we have been able to achieve a remarkable success? Ours is a growing economy. We started with a very low pace. With every successive plan there has been a cost push. As one of our hon. Members has said that when we put more money into the economy, when there is thrust for development and when (here is deficit financing octainlv there wouV) be inflation. This infla-tionary trend is not only in India, but

we can also see in our neighbouring and o^her countries. Is it not a fact that in recent years even some of the very advanced countries where they have regulated economies, there is . inflation? They have also got much bigger inflation than what we have. Is it not a fact that due to the over-all economic policy of the Government, particularly, during the last four five years, we have been able to reduce the inflation to a manageable level from the prevous years 1983-84? According to the inflation figures which have been quoted by the hon'-ble members and also quoted in I ho statement of the hon'ble Minister, we have not been able to contain inflation from 1983-84 better in 1984-85 and much better in 1985 during the last couple of months time. The question is; it is a complex subject. Ours is a country in which when we measure is economic achievements, we will also have to take into consideration the population rise. From 34 crores, we have now reached 70 crores. When we talk of per capita income, we will have to take into consideration the situation with reference to the population growth and therefore we cannot one sidedly say that we have not been able to achieve the goals of per capita income. Certainly, we fa to raise it further but the question is what successively we have been able to do. We cannot close our eyes to the successive achievements. We should see everything with open mind and assess the deficiencies and the difficulties we are facing today and' we must have determined efforts to remove them and that is what the Government is doing. This House had a discussion about shortages of these commodities. We had very hec-t;c debate on this issue that the sugar is not available. There are other commodities "which are not available in rural areas. Now is it not a fact that they are available today? It is a fact that they are available at higher prices and certainly we should make efforts to reduce them and the direction must be there because it affects every member of the House, every common man ' in the country but the question is on the policy front. I am surprised after having said all that, whether up till now, in the debate, there has been any single suggestion to this effect? Where is the change needed in the Policy front; where is the change needed in the implementation agencies in respect of essential commodities?

Hon'ble member have said simply that adequate steps should be taken effective measures should be taken This one can understand. These go much more so far as the implementation part is concerned. So far as the policy frame is concerned, policy is well known. In a country where we have mixed economy and planned economy and particularly when we find that year year, certain parts of the country are affected by droughts, certain parts are affected by floods. Even today, what is the situation? Even this morning the Hon'ble Finance Minister explaned to us that ths year on account of drought and floods itself, a very substantial amount has already been distributed to the various states and even then, there are a number of States which are asking for aid which is quite natural when there are natural calamities. There are natural features. There are natural limitations also. Nobody in the House will plead that the prices should not be contained. If we have been able to contain particularly to a certain level, the wholesale prices what is the reason that the retail prices have not been controlled and we have not succeeded in it. This we have to see with open mind and not from the party lines but from the common man's point of view and our own colleagues have said here that they feel concerned about it. I share their concern. 1 feel concerned about it but the question is: if there arc deficiencies in imoementation. Of there is maldistribution, what effective steps the Minis-

[Shri Rameshwar Thakur]

try should take, the Mhister should take, to ensure that the essential goods reache the common man at a price wluch is reasonable; and whether it is possible as has already been said by the Hon'ble Finance Minister that foodgrains will be supplied to the common man, weaker sections of the people, people below the poverty line at a certain concessional price? I would like to make two suggestions. One is that the essential commodities of day-to-day use. for the common man must reach all parts of the coun-try, throughout the year.

That lias to be ensured by the adi-ministration at the Central and State levels. Secondly, where there are middlemen who want to make undue profits, where here is a hoarding and blaekmarketing to some extent, if they are the reasons for the price rise, we should see whether there should be any effective machinery to ensure that we are able to contain this part of the pr.'ce rise which is not natural. When there is production, when there -is availability of goods, still prices are very high, even in he case of ordinary things like vegetables. If there is enough supply, why should the prices rise? There are other essential commodities. Why should the prices rise when there is enough supply? Is there any deficiency in the machinery? I would urge the hon. Minister to take of the machinery which is regulating these things at the State level as well as the Central level, so that the common man's interests are not affec'ed on account of a defective machinery. May be a lot of improve-ments are needed in the machinery.

The next aspect is the economic policy which will give us or ensure a regular supply of essential cotnmodi-ties and their production on a long-term oolicv frame. Why should we have to imoor* certain things? The question is whether, In a country like ours where the agrculturists are very much advanced, with infrastructural aid and scientific and technological assistance and also with the assistance of the State Governments and the Central Government, we cannot possibly ensure that we are self-sufficient, as in (foodgrains, in other commodities also That will be the long-term solution. We must try to bring about self-sufficiency in other essential commodities where we have deficits today. Why should we import at higher prices? Why should we sub-sidise commodities? Can we not help our agricultural production and other productions here to ensure that we are able to supply them at reasonable prices and that the prices do not rise on account of the fact that we have a scarcity or we are importing them at higher prices? therewise there will be room for hoarding and blaekmarketing.

Lastly, if there is a real deficiency in the machinery— think there is— then should we not take more strict measures? For instance, there was so much concern when the income-tax rates were reduced, that it would benefit onlv a certain category of per sons. But today we find that instead of the budgeted 12 per cent, there is already an increase of 26 per cent in the collection during the last six months in incomet-ax. That was because the machinery has been tightened and on a certain reasonable basis, the tax rates had been brought down so that the people are able to declare more income. If it could be done in one field, does not the Government think that in this field of essential commodities also, where the largest number of citizens are affected, the machinery could be sufficiently tightened? No sympathy should be shown to any person who plays with the lives of the common people, to thoso who are trving to make undue profits out of a situation which is not called for. which is not realistic and wheh affects the common: man and benefits only a certain class of people.

With these words, Madam Deputy Chairman, I would like to say that if one objectively analyses the matter, one would feel that the policies followed during the successive Five Year Plan are very very sound. There have been deficiencies, I know, in certain cases where we have not been able to achieve our goals. But during the Seventh Five Year Plan, with our experience of the earlier failures and deficiencies, we should eb able to take sufficient remedial steps. The Seventh Five Year Plan, about which mention has been made and which has been recently approved by the National Development Council, is going to be a much bigger Plan where the outlay will be much more than the combined outlays of the first six Five-Year Plans. We have a greater stake. As our Prime Minister said, we have to move with fa^er growth and development, with a determined will and effort. Any plan can succeed only if all sections of the community make a joint effort. It is not a question of Government alone. Anywhere in the world plans can succeed only when the entire people are involved in the implemntation,, all the machinery is involved. I am sure we will be able to succeed and achieve the Seventh Plan targets. All efforts should be made to ensure that we are able to raise our economic development to ensure that we are able to in-creas our production, to ensure that there is proper distribution of the facilities, so that the quality and standard of Jife of the common man is improved.

श्री अश्विनी कुमार (बिहार): माननीय उप सभापति महोदया, हम लोग विचार कर रहे हैं कि इस समय कुछ वस्तुओं के दामों में बहुत जबर्दस्त बढ़ोत्तरी हुई है। अभी-अभी मेरे पूर्व जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने बहुत अच्छी आशा दिखाई कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। उस समय उन्होंने कहा कि इसमें सब को सहयोग देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सरकार से पूछना चाहता हूं कि सहयोग वह किसका मांग रहे हैं? पार्लियामेन्ट तक का सहयोग सातवीं प्लान में लिया नहीं गया है। प्लान पास हो गया है। नेशनल डिवेलपमेंट काउंसिल ने पास कर दी है। अब वह पार्लियामेन्ट के सामने आयेगा फेथ एकोंपली, राय जानने से कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसका भी ढंग होता है, पार्टीसिपेशन का भी कोई ढंग होता है। अगर कोई ढंग होता है तो पार्टीसिपेशन भिन्न-भिन्न लेवल से लिया जाता है। राय क्या हो, क्या नहीं हो और उसके बाद प्लान बनता है। हमारे जो प्लानिंग चल रही है जिसके कारण यह प्राइज राइज हो रहा है। दिल्ली के तंबूरे के ऊपर और वहां सेंट्रिकल डाउन होता है कि यह करो, यह करो और वह करो। आदेश दिए जाते हैं। लेकिन उसके अन्दर पार्टीसिपेशन नहीं होता, लोगों का योगदान नहीं होता, उनको लगता नहीं है कि यह उनका प्लान

SHRI RAMESHWAR THAKUR: The outline of the Seventh Plan was placed before the House and was discussed at some length by various sections of the House. So, 1 do not think it is correct to say that it was not brought before the House,

श्री अश्विनी कुमार: आज यह मेरा ही कहना नहीं है। यह मुख्य मंत्रियों जो उसमें बैठे थे उन्होंने भी कहा है हमारे सामने फेथ एंकोपली है। मुख्य मंत्रियों तक को उसमें लिया गया है। यह उनके बयान हैं। आप देखिए कि क्या यह बात वास्तव में सही है। अगर देश को इकोनोमी को उठाना है तो आप सब का सहयोग लें। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि दलगत प्रश्न नहीं होना चाहिए। दल को भी छोड़ दीजिए। परन्तु सरकार का जो तंत्र है, उनके मंत्रिमण्डल के नीचे तक का जो तंत्र है, पंचायत तक की समिति जो है प्लानिंग के अन्दर लेकिन मूल-भूत नीचे से लोगों का, जनता का पार्टीसिपेशन नहीं है। ऊपर से प्लान थोपी जा रही है। इसके कारण समस्या आ रही है। प्राइस बढ़ रही हैं। सरकार की ओर से हमेशा जब भी प्राइस राइज का प्रश्न आया है तो एक ही उत्तर आ जाता है कि जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या के बारे में तो हर कोई जनता है कि यह बढ़ेगी। हर व्यक्ति घर में जानता है कि मेरे लड़का हुआ है। अगर उसकी शादी होगी तो बच्चे भी होंगे। अगर वह प्लान नहीं करता है तो यह प्लान करने वाली की समस्या है। फैमिली प्लानिंग जितनी सफल होनी चाहिए उतनी नहीं हुई, यह बात स्पष्ट है। यह सरकार की प्लानिंग का दोष है। अगर आप जनता को दोष देकर, जिन्होंने कि बच्चे पैदा किए हैं, दोष देकर छूटना चाहेंगे तो मेरा यह कहना है कि दिस इज नाट ए वायंरूर एलेबी। हमको पता है कि किस अनुपात से जनसंख्या बढ़ रही है। हम प्लानिंग के प्रयास से देख रहे हैं।

श्री जनार्दन मिश्र : माननीय सदस्य ने फैमिली ही नहीं बनाई तो वह प्लानिंग क्या करेंगे ?

श्री अश्विनी कुमार : हम इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, यही तो मेरा कहना है।

उप-सभापति: बाकी लोग प्लान करते हैं, यह फैमिली करते हैं।

श्री अश्विनी कुमार: उप-सभापति महोदया, आज आम आदमी के उपभोग की जो चीजें हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं। और जो सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जो पावर्टी की लाइन के नीचे वाला व्यक्ति है, गांवों में रहने वाले हैं, जो जनसंख्या का 80 प्रतिशत है उसकी चर्चा नहीं होती और ऊपर का जो 20 प्रतिशत है उनकी चर्चा होती है। पिछले वर्ष बताया गया कि इनकम टैक्स पेयर 44 लाख हैं, इस वर्ष शायद 70–80 लाख हो जाएंगे। 70 करोड़ की जनसंख्या में 70 लाख ऐसे आदमी हैं जिनकी आमदनी 25 हजार से ऊपर है। यह हमारी सम्पन्नता है। छोटी सी सम्पन्नता का दिया टिमटिमा रहा है और उस दिए के नीचे झुग्गी–झोंपड़ी में रहने वाली लाखों जनता सांस तोड़ रही है। कहा जाता है कि दिल्ली–बम्बई में 80 प्रतिशत स्लम–ड्वेलर्स हैं। यह समान्नता क लक्षण है ? उनके लिए दाम बढ़ रहे हैं। इससे उनकी रोजी–रोटी में अन्तर आता है। इतना ही है कि आज उनके खाने में दाल है, रोटी है, नमक है, प्याज है, कल दाल गायब हो जाती है, सब्जी गायब हो जाती है, खाली नमक और प्याज के साथ खाने के लिए रोटी रह जाती है। उनके ऊपर इसका सबसे बड़ा एफेक्ट पड़ता है। आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसी नीतियां बनाएं जो 80 प्रतिशत के लिए हों। आज 5–7 प्रतिशत के लिए सरकार नीतियां बना रही है। 5 प्रतिशत के लिए इम्पोर्ट खुला है, हाई टेक्नोलोजी 5 प्रतिशत के लिए है। क्या परिणाम हो रहा है। जाबस कम होते जा रहे हैं। टिस्को के अन्दर टेक्नोलोजी माडर्नाइजेशन हो रहा है, 45 हजार में 15 हजार छंटनी के कगार पर आ गए हैं। उनकी छंटनी नहीं की जाएगी, लेकिन रिटायर होने पर उनकी जगह दूसरे नहीं रखे जाएंगे।

दाम एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से बढ़ते हैं, सप्लाई और डिमांड का प्रश्न उतना नहीं है। जहां तक चीनी के दाम की बात है, 82-83 में 82 लाख टन चीनी हुई, लेकिन गन्ने का दाम नहीं मिला, घटना शुरु हो गया। किसान को जो चीज उपलब्ध कराई जाती है, डीजल, ट्रैक्टर उनके दाम बढ़ाते चले जाते हैं, इनपुट के दाम बढ़ते हैं, आउटपुट के दाम नहीं बढ़ते, इसलिए चीनी घट गई। आप विदेश से मंगा रहे हैं। विदेश से आप 1 रुपए किलो चीनी मंगाते हैं। उसको आप किस भाव बेच रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि 1 रुपया किलो चीनी 5 रुपया किलो बेच कर सरकार क्या प्रोफिटियरिंग नहीं कर रही है। आज हम चीनी मंगा रहे हैं। हमें पता था कि चीनी कम होगी। पहले मंगाई जा सकती थी। उसमें विलम्ब किया गया और अखबारों में छपा है कि उस विलम्ब के अन्दर बड़े-बड़े घोटाले हुए हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार स्पष्टीकरण करे। एक और चीज जानना चाहूंगा कि जब 10 लाख टन चीनी मंगा रहे हैं तो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, 25 हजार टन एक्सपोर्ट कर रहे हैं–इसका क्या कारण है। जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है। हर वर्ष 12 से 15 प्रतिशत चीनी की खपत बढ़ रही है। इसके लिए गन्ना के उत्पादन के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में सारे देश की बात मैं नहीं जानता, पर बिहार की बात जानता हूं कि गन्ने की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। जितनी चीनी मिलें हैं वे बन्द होती जा रही हैं। 16 मिलें के किसान को किसानों को अच्छा बीज सरकार ले चुकी है। उनमें से भी बन्द हो रही हैं। गन्ना अधिक हो और गन्ने को अच्छा बीज मिले इस दिशा में सरकार विफल रही है। गन्ना अच्छा नहीं है। महाराष्ट्र में रिकवरी अच्छी है। उत्तर प्रदेश और यहां के गन्ने की नहीं है। जो सेस और यहां के गन्ने की नहीं है। जो सेस लिया जाता है गन्ने की बढ़ोतरी के लिए वह भी नहीं पहुंचता, रास्ते में रह जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि देश के अन्दर विकास हो तो आज हमारे जो डेवलपमेन्ट के प्रोग्रामों में लीकेजेज हैं उनको रोकने का प्रयास करें। बिहार के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि ब्लाकों में जो काम हो रहा है उसके लिए अगर सरकार सौ रुपए देती है तो धरातल पर 34 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होता है बाकी सारा रुपया बीच में ही बंट जाता है। इस की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

शुगर का जो दाम बढ़ रहा है उस का एक कारण है। शुगर मिल मालिकों को 225 करोड़ का इस साल की जेब से जाएगा यह सोचने का में फायदा होगा। यह फायदा किस विषय है और आज जो कामन मैन को 225 करोड़ का इस साल में वनस्पति के दामों के बारे में मेरे के लिए क्या हो रहा है। अन्य मित्रों ने भी चर्चा की है। इस सम्बन्ध में मैं केवल एक बात आप से निवेदन करना चाहूंगा जो मेरे सामने समाचार पत्रों के माध्यम से आयी है कि योरोपियन मार्केट बटर आयल को बहुत बड़ी मात्रा में भारत सरकार को बेचने का प्रयास कर रहा है। लगभग 50 हजार टन प्रति वर्ष वह देने के लिए तैयार है और लगभग 10 रुपये प्रति किलो के आधार पर वह सरकार लेने भी जा रही है और मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि वनस्पति इण्डस्ट्री चाहती है कि वह उन को दे दिया जाए और वह वनस्पति के रूप में उस को कंवर्ट कर के बेचें। मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा कि अगर यह बटर आयल दस रुपए प्रति किलो के मूल्य पर आप को मिल रहा है तो यह आम जनता को फेयर प्राइस शाप्स के माध्यम से दिया जाए और जो वनस्पति है वह आज 17, 18 रुपए के भाव पर मिल रहा है और मस्टर्ड आयल उस से थोड़ा कम है। मेरा सुझाव है कि बटर आयल उन को दे कर उन

[श्री अश्विनी कुमार]

का घर न भरा जाए और आम जनता के लिये उस का उपयोग किया जायगा ।

इस विषय पर अन्य मित्रों ने जो बहुत सी चर्चा की है मैं उस में दुबारा न जा कर यही कहना चाहता हूं कि केवल ज्वार और ईडीबिल आयल को छोड़ कर और सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और पिछले साल से अधिक बढ़ रहे हैं । माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े किए कि इस वर्ष इस महीने में पिछले वर्ष से दाम कम बढ़े हैं यह कोई समाधान का विषय नहीं है । आज गरीब जनता का हाल भयंकर है । जो बंधी हुआ आय के लोग दिल्ली में रहते हैं उन में से एक सज्जन मुझ से सदा मिलते जुलते रहते हैं और उन को एक हजार रुपया उन्होंने मुझे बतलाया कि पिछले 3 से दाम बढ़े हैं उस से 150 रुपए को उन महीने में जितनी चीजों के जिस तरह मासिक की तनख्वाह मिलती है । 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो रही है के बजट में बढ़ोत्तरी हो गयी है । केन्द्रीय सरकार को स्वयं पता है कि प्राइस इण्डेक्स कहां जा रहा है । सेंट्रल गवर्नमेन्ट का डी ए कहां जा रहा है । इस के पीछे एक बहुत बड़ी पोलिटिकल डिसीजन्स आफ दि सेन्टर है । अगर तो शायद मूल्य वृद्धि रोकने में सुबिधा यहां के, सेन्टर के डिसीजन्स ठीक होंगे होगी । और ऐसा नहीं है कि हमेशा हो मूल्य वृद्धि हुई है या होती रही है बीच-बताना चाहता हूं कि 1977 से 1980 बीच में मूल्य वृद्धि रुकी भी है । मैं तक मूल्यों में केवल ढाई प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और उस के बाद प्रत्येक वर्ष 12 से 15 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है । इस के बारे में आप को विचार करना चाहिए । यह केन्द्रीय सरकार की नीतियों पर निर्भर करती है और आप के माध्यम से मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जो प्रश्न मैंने उठाए हैं उन का वे उत्तर दें और केन्द्र में जो गड़बड़ी है उस को ठीक करें ताकि आम आदमी को, गरीब आदमी को, देश की 80 प्रतिशत जनता को जो महंगाई बढ़ रही है उस से कुछ राहत मिले ।

श्री विट्ठल भाई मोतीराम पटेल (गुजरात): मैडम डिप्टी चेयरमैन, महंगाई बढ़ी है इस में कोई दो रायें नहीं हैं लेकिन यह महंगाई बढ़ने की वजह क्या है इस को भी देखना चाहिए । जब गुरुपद स्वामी जी ने कहा कि रियलिटी देखनी चाहिए कि किस बजह से महंगाई बढ़ चाहिए तो हमें भी रियलिटी देखनी रही है । महंगाई बढ़नी के लिए सिर्फ सरकार को ही जिम्मेदार बनाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जैसे मिश्र जी ने कहा कि तमाम चीजों के भाव बढ़ गए । कोयले का इस्पात का भाव बढ़ गया तो इस्पात के कारखाने किस से चलते हैं । कोयले की खान किस की है। सरकार की है और वह पब्लिक सेक्टर में है और हर साल वहां वर्कर्स आन्दोलन करते हैं कि उन की तनख्वाह बढ़ाई जाए । जब उन की तनख्वाह बढ़ेगी और उन की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो चीजों का भाव आप तनख्वाह बढ़ायेंगे तो परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो भाव भी चीजों के भी बढ़ेगा । तो यह एक पूरा चक्र है । बढ़ेंगे और भावों को बढ़ने से कोई नहीं रोक पायेगा । भाव को रोकने का उपाय केवल प्रोडक्शन बढ़ाना है और उसके लिये जो इंसेंटीव देना है वह देने चाहिए । जरूरत पड़े तो इंडस्ट्री को माडर्नाइस करना चाहिए और माडर्नाइस करने से प्राइसेज कैसे कम होंगी? लेकिन जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी हम प्राइसेज को कम कर पायेंगे । मिश्रा जी ने पुराने गांधी की बात कही । पुराने गांधी उस समय सही थे । नए गांधी आज सही हैं । नए गांधी चाहते हैं कि प्राइस कन्ट्रोल हो तो कास्ट् प्राइस कम करनी पड़ेगी । नये गांधी जो कर रहे हैं वह ठीक कर रहे हैं क्योंकि देश को माडर्नाइजेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं । आज पुराने गांधी की नीति नहीं चलेगी क्योंकि जमाना बदल गया है, सारी दुनियां बदल गई है, टैक्नालाजी बदल गई है । तो पुरानी बातें सोचने का कोई फायदा नहीं होगा । इसके बदले में यह सोचना चाहिए कि हड़तालें कम हों, स्ट्राइक कहीं पर भी न हों । अगर यह

कर दंगे त मेरे ख्याल से उसका प्राइस पर भी असर पड़ेगा । प्राइस कम करने के लिए हम सब को यह सोचना कि प्रोडक्शन कहीं भी नहीं रुकना चाहिए ।

दूसरी तरफ आज एल.आई.सी. का कर्मचारी तीन हजार रुपया पाता है, बैंक वाला चार फिगर में पाता है, सरकारी कर्मचारी चार फिगर पाता है लेकिन जो गांव में रहता है जो आदिवासी और हरिजन है, वह नारा नहीं लगाता है जो सबसे कम पाता है । वह सफर करता है । मैं गवर्नमेन्ट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कल ही एनाउंस किया कि उनको सबसिडाइज्ड रेट पर एसेंशल कमोडिटीज, अनाज, दालें, चावल वगैरह मिलेंगी । खाने की चीजें, जैसे गुड़ है, चीनी है वह सबसिडाइज्ड रेट पर दी जा सके तो यह सबसे अच्छा होगा । लेकिन वह बेचारे नारा नहीं लगाते हैं । नारा वे लगाते हैं जो हवाइट कालर हैं, जो बैंक वाले हैं या एल. आई. सी. वाले हैं । वे जलूस निकालते हैं जिनकी जारूरत बढ़ गई हैं ।

किसी ने कहा कि 1951-52 में क्या भाव था । मैं जब छोटा था तो एक पैसे में तीन दियासलाई की पेटियां मिलती थीं, एक रुपए में 10 पौंड चीनी मिलती थी । तो उस जमाने की बात करने से आज क्या फायदा ? उसके बाद कितना बदलाव हुआ है, कितनी पापुलेशन बढ़ी है । तो यह सब देखते हुए मैं मानता हूं कि सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है । हमारा ही दोष है कि हम तीन हजार पाते हैं फिर भी आन्दोलन करते हैं । तीन सौ रुपए पाने वाला आन्दोलन नहीं करता है, लेकिन तीन हजार वाला करता है । तो वह कंज्यूमर्स के ऊपर ही पड़ेगा। इसलिए प्राइस बढ़ती है । इसलिए सोचने की बात यह कि प्रोड्क्शन कैसे बढ़े । मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसान के भाव की जब बात आती है तो अग्रिकल्चर प्राइस कमीशन वाले बोलते हैं, रिजर्व बैंक वाले बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले बोलते हैं कि किसान का जो प्राइस है उसको बढ़ा दिया जाएगा तो इनफलेशन बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो भाव बढ़ जाएंगे । एल.आई. सी. वाले, बैंक वाले यदि ज्यादा मांगते हैं तो उससे भाव नहीं बढ़ते होंगे यह गलत बात है ।

उपसभाध्यक्ष [डा. (श्रीमती) सरोजनी महिषी] पीठासीन हुई

किसान की जरूरतें ज्यादा नहीं हैं । उनको तो रोटी व सब्जी तथा ट्रेक्टर के लिए डीजल तथा खेतों के लिए बिजली मिल जाए तो वे सन्तुष्ट रहते हैं । तो उनकी वजह से कोई प्राइस नहीं बढ़ेगी ।

महोदया, स्टेटमेन्ट में कहा गया है कि गन्ने का 14 या 16 रुपया प्राइस देने से शुगर की प्राइस बढ़ानी पड़ी । यह बात मेरी समझ में नहीं आती । सबको पता है कि पिछले साल गन्ना का 22, 28 का भाव दिया था, फिर भी शुगर मिल वालों को प्राफिट हुआ था । तो 14 या 16 रुपए देने से तो ज्यादा प्राफिट होना चाहिए। यह अरिथमैटिक कहां गलत है, इसको चैक करना चाहिए और 14 या 16 रुपया का गन्ने का दाम देने से शुगर के भाव नहीं बढ़ने चाहिए क्योंकि उससे ज्यादा देने पर भी शुगर मिल वालों ने प्राफिट कमाया है । इसलिए गवर्नमेन्ट को शुगर के बारे में सोचना चाहिए और फेयर प्राइस शाप्स में जो चीनी दी जाती है उसका तो भाव नहीं बढ़ाना चाहिए । जो आपने वीकर सेक्शंस के लिए सबसिडाइज किया यह अच्छा किया, लेकिन जिनकी आमदनी कम है, जैसे पुलिस वाले हैं जिनको 700 या 800 रुपया तनख्वाह मिलती है, उसको उसी में अपने परिवार का गुजारा करना पडता है । कई स्टेट्स में ऐसा है, मैं पंजाब में गया हूं, मैंने देखा है वहा के जो पुलिस कांस्टेबल हैं उनको तीन साल में एक यूनिफार्म दी जाती है और महीने में ढाई रुपए वाशिंग एलाउन्स, पालिश एलाउंस बेल्ट पालिशिंग एलाउन्स के लिए दिए जाते हैं । ढाई रुपए में क्या होगा ? इस ढाई रुपए में क्या पुलिस वाला अपनी यूनिफार्म धुला सकता है? जैसा हम डिफेंस में देखते हैं कि उनको एसेन्शियल कमोडिटीज रीजनेबल प्राइस पर देते हैं उसी तरह से इन पुलिस

[श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल]

वालों को भी दी जानी चाहिए । जब इनको इतना कम पैसा मिलेगा तो करप्शन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे । मेरा कहना है कि वीकर सेक्शन के लिए या जिनकी आमदनी कम है चाहे गवर्नमेंट सर्वेन्ट हो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए । मिश्रा जी ने अभी बताया था कि हिन्दुस्तान में भाव बढ़े हैं और डेमोक्रेटिक कंट्रीज में बढ़े हैं कम्युनिस्ट कंटरीज में उतने दाम नहीं बढ़े हैं । यह गलत बात है । मैं यूरोप और कम्युनिस्ट कंटरीज में गया हूं मैंने देखा है एक ब्रेड की कीमत यहां से तीन गुनी है । यदि ऐसा नहीं होता तो वहां रेवेलूशन क्यों होता । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि प्रोडेक्शन को कहीं नहीं रोके । एग्रीकल्चर प्रोडेक्शन ज्यादा होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडेक्शन ज्यादा होगा तो प्राइसेज कन्ट्रोल में आयेगी । मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि किसी तरह भी प्रोडेक्शन को न रोके ताकि प्राइस कन्ट्रोल में आ सके। धन्यवाद ।

SHRI J. P. GOYAL (Uttar Pradesh): Madam Vice-Chairman, I want to bring to your notice the position particularly about sugar. With regard to levy sugar the increase is 48 paise per kg. But regarding the other sugar also it is 10 per cent per kg. Now, the millowner, sugar mdllowners, they used to, till now, give 65 per cent of their products for levy sugar to the Go.vernment and 35 per cent was to be sold in the open market. Now, I understand, it is 55 per cent for the levy sugar and 45 per cent for the open market. I want to ask the hon. Minister why this ratio has been "hanged recently? I also want to know why there is the double pricing system regarding sugar. Is it not a fact that there is the possibility of black-marketing in sugar by the levy sugar being diverted to the open market because a number of people, particularly in the villages, do not get sugar. I understand that in the villages even thnn<?h they might be having ration r>ards. thev are not given sugar. So, this is the position regarding sugar. "eTtirdin? vanasoati ghee, recently the price of 15 Kgs. tin of ghee has been increased by Rs. 25.50. It means that there is an increase of about Es. 1.70 per kg. The hon. Minister in his statement has now disclosed as to why this increase in the price of vegetable ghee has taken place.

Regarding cloth, for example, the mills are producing fancy cloth which can fetch high prices, whereas the cloth for the poor people, which may be called the janata cloth, is not being produced at that rate at ' which is should be produced. We have been discussing price rise almost in every session and almost every session the prices have been rising in the country and the House has been discussing rise in prices and every time there are excuses that it is happening because oi the rise in population or this failure or that failure that the prices have risen. But the rise in pi-ices has always affected the poor people living in the villages and also in the 3 P.M. towns. About 90 per cent 01 our population are living be low the poverty line and they ar< affected by the price rise. This pheno menon has to be checked. My owi feelings is, when we have legalised th< donations by millowners and com panies to political parties, we canno check this price rise; Government can not check it; it cannot check hoarders the blackmarketeers and the capitalis class because in the elections, the rul ing party particularly is given dorw tions of black money. In the last elec tions to Lok Sabha in 1984 and also in 1985. the ruling party has spen money like water. It has never plained from where this money ha comes . . . (Interruptions).

SHRIMATI MONIKA DAS (Karn; taka): What is '.his discussion *(Intel ruptions)* How much did you spent You spent more than anybody else.

SHRI J. P. GOYAL: You may sa something. Those who are affected the price rise draw a legitimate ence that because the ruling part has taken donations from the mil owners, it cannot check the ri«e i prices. Otherwise, why sdould

allow the millowners to charge Rs. 1.30 per kg. on vanaspati more. It is not consumed by richer people; only the poor people who cannot afford pure ghee, depend on vanaspati, and the price of this vanaspati is being increased. . . *(Interruptions).* Is there no relationship of the price rise with the fact that the ruling party which is running the Government has taken lot of money, crores of rupees from the millowners, the hoarders and the. blackmarketeers . . . *(Interruptions).*

SHRIMATI MONIKA DAS: How you have taken. You also say that.

SHRI J. P. GOYAL: Have you ever explained how much money, you have taken? Is there no relationship of the price rise with this phenomenon. So. this will go on. All our please will fall on the deaf ears of the Government. It will never cure the economy of the country. The poor people will get poorer and the rich, the richer. Now more than 50 per cent are living below the poverty line and it will go up to 70 per cent . . . *(Interruptions).*

SHRIMATI MONIKA DAS: As if they have not taken. He is accusing the ruling party. How much they ha taken?.

SHRI SUSHIL CHAND MOHUNTA (Haryana): Try to hear the bitter truth; have patience.

SHRIMATI MONIKA DAS: You have taken more money than the ruling party people. Madam, he is supposed to speak on the price rise not this way.

SHRI J. P. GOYAL: After all, we are members of the opposition; we cannot sing to the tune of the Government.

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Thank you, Mrs. Monika Das, *for the confession made by you.

SHRI SUSHIL CHAND MOHUNTA: You tell, us, how much money you have taken.

SHRIMATI MONIKA DAS: You give us your figure first. Let everybody know.

SHRI J. P. GOYAL: I am just illustrating the point. In our Parliament, for example, I have got with me a chart showing prices of the canteen which is being run by the Railways catering department. In 1981, for example, chicken roast with boiled vegetable was costing Rs. 6.50. This was in 1981. Now, it is more than Rs. 9. It was increased last month. Then, for example, in the case of a non-vegetarian meal in our canteen here, it was Rs. 5.60 and now it has been increased to Rs. 8.95. We are also affected, Members of Parliament. (Interruptions) An honest Member of Parliament is also affected who is not getting money underhand from the capitalist class. Therefore, let the Government today swear that they wlil not take any money from the capitalist class, the hoarders and the blackmarketeers. Unless they do it, they will not be brave enough to tackle the price situation. These are my submissions.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHR-MATI) SAROJINI MAHISHI]: Shri Raflque Alam. I would request hon. Members not to interrupt. Otherwise, we will be taking more time on this discussion.

श्री रफीक आलम (बिहार) : महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि मंहगाई बढ़ी है । एक मिस्ल मशहूर है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की और मंहगाई बढ़ती गई ज्यों-ज्यों सरकार ने उसको कम करने की कोशिश की । इसका क्या कारण है इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा । लेकिन यह बात हकीकत ही है और यह कोई नहीं कह सकता कि मंहगाई नहीं बढ़ी है । मुझे अपने गांव जाने का मौका मिला । मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो गांवों की हालत है । वह बहुत खराब हो रही है । चीनी तो लोगों को मिलती नहीं है । सबसे बड़ी मुश्किल बात तो यह हो गई है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक से नहीं चल रहा है । सप्लाई इन्सपेक्टर मोटर साइकल पर चलते हैं और उससे ऊपर जो

[श्री रफाक आलम]

ए. डी. एस. ओ. है वह कार पर चलते हैं। वहां से उनके पास इतना पैसा आता है? जब तक बिजनेस मैन और हमारे इन आफिसरों की मिली-भगत रहेगी प्राइस कन्ट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोगों ने वहां कहा कि जो डीलर है वे राशन दुकानों पर लाते भी नहीं हैं, न चीनी लाते हैं, न तेल लाते हैं वहीं उसका स्टाकिस्ट को, बेच देते हैं। नतीजा यह होता है कि वे राशन की चीजें बाजार में ऊंचे भाव से बिकती है। मैं इस सिलसिले में सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार हिम्मत से काम ले ताकि यह जो बढ़ती हुई मंहगाई है यह घटे। आज मैं यह खुद गया था लंच के लिये। सोचता था कि 10 रुपए में मिल जायेगा। लेकिन लंच के 20 रुपए ले लिये। अगर मंहगाई घटी है तो इसको 5 रुपए होना चाहिए था। इस पर भी कन्ट्रोल होना चाहिए। 20 रुपए में एक एम.पी. किस तरह से खा सकता है। .... (व्यवधान)....आज जो सबसे बड़ा सवाल है वह यह है कि जो चीजें कारखानों में बनती हैं, उनकी कीमत बढ़ती जाती है लेकिन जो चीजें काश्तकार पैदा करता है उसके दाम घटते जा रहे हैं। मैं उस इलाके से आता हूं जहां जूट पैदा होता है। पिछले साल 400 रुपया मन जूट बिका था। इस बार भी किसानों ने जूट लगाया। एक मन जूट पैदा करने में किसान का 150-175 रुपए खर्चा होता है लेकिन इस साल उसका भाव 60 रुपए मन है। नतीजा यह हुआ कि जूट जलाया गया। जो गोल्डन फाइबर कहलाता है, जो फारेन एक्सचेंज अर्नर कहलाता है उसकी यह हालत है। इस कारण से काश्तकार बहुत तरह से परेशान है। हमारे यहां पूर्णिया, दरभंगा और सहरसा आदि जगहों पर काश्तकार तबाह हो गये हैं, बरबाद हो गये हैं। काश्तकारों को उनकी चीजों की कीमत ठीक नहीं मिल रही है। हमारे देश में 80 प्रतिशत काश्तकार रहते हैं। अगर उनकी आमदनी घट जायेगी तो इस मुल्क में खुशहाली कैसे आयेगी। इसलिये सरकार को इस जनक बात है। अगर कुल आबादी का 80 प्रतिशत भाग कोई चीज खरीद नहीं पायेगा तो हमारी मिलें भी बंद हो जायेंगी, हमारे कलकारखाने बंद हो जायेंगे और दुकानें भी बंद हो जायेंगी। इसलिये सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए और उनकी चीजों की कीमतों में इतना मारजीन अवश्य रखें ताकि उसको भी कुछ मुनाफा हो सके। काश्तकारों ने जो बलिदान इस मुल्क को दिया है वह किसी से कम नहीं है। 1943 में जब हिन्दुस्तान एक था, न पाकिस्तान था, न बंलादेश था, उस वक्त हिन्दुस्तान की आबादी लगभग 40 करोड़ थी। 1943 के फेमिन में सिर्फ बंगाल में 10 लाख आदमी मर गये थे लेकिन सरकार ने कोशिश की और पैदावार बढ़ी है उसमें कोई शक नहीं है और जो बात हकीकत है उसे कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिये। लेकिन अब हमारे देश की आबादी बढ़ कर के 71 करोड़ हो गई है। बढ़ती हुई आबादी का एक बहुत बड़ा मसला हमारे सामने है। प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन, ये दोनों जब तक मुनासिब नहीं होंगे हम कितना ही पैदा करें वह कम है। इसलिए फेमली प्लानिंग के बारे में हमारे विरोधी दलों के लोग कह रहे थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब 1977 में सरकार ने सोचा कि लोग कितना ही पैदा करें लेकिन फेमली प्लानिंग जब तक नहीं होगा जब तक तो हमारी पैदावार उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। मुलक की आबादी बढ़ती जा रही है, इसलिए सब से पहले मुलक की बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करना चाहिये। मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं कि जो 1977 के इलैक्शन में हुआ बजाय उस में सहयोग देने के 1977 के इलैक्शन में विरोधी दल के लोगों ने पूर्णिया जिला में कहा कि मुज्जफ्फरपुर जिला में पांच हजार लोग बंधीकरण के कारण मर गये और मुज्जफ्फरपुर जिला में यह कहा गया कि मुज्जफ्फरपुर जिला में नहीं पूर्णिया जिला में मारे गये, पूर्णिया जिला की बात सहरसा जिला में कही गई और सहरसा जिला की बात किसी दूसरे शहर में कही गई। इस तरह से गलत अफवाहें विरोधी दल के लोगों ने फैलाकर लोगों को अन्धकार में डाला जिसका रिजल्ट आप सब ने 1977 में देखा। सरकार ने अगर कोई काम अच्छी

।रिया से भी किया लेकिन उस वक्त इलेक्शन के प्वाइंट आफ व्यू से सोचा जाए तो कोई काम नहीं हो सकता है। इसलिए जहां मुल्क का सवाल है, लोगों का सवाल है, हम सब को एक होना चाहिये चाहे किसी पार्टी से किसी जाति से किसी धर्म से ताल्लुक रखता हो । सब को यह सोचना है यदि मुल्क बचेगा तो हम बचेंगे । इसलिए नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे । इसलिए अभी जो बढ़ती हुई मंहगाई है उसको मन्त्री जी कंट्रोल करने की कोशिश करें। अभी मैं आपको दिल्ली की बात बताना चाहता हूं । कल मैंने अपने नौकर को फेअर प्राइस शाप पर भेजा । तीन दिन से वापिस आ रहा है कि साहब चीनी नहीं मिली । अब अगर दिल्ली में यह हाल हो तो बताइये गांवों का क्या हाल होगा । हमारा जो एफ. सी. आई. है यह व्हाइट एलीफेंट है इसको कंट्रोल कीजिए नहीं तो यह सब को भूखा मार देगा । दूसरी बात यह है कि लोअर तबके को आप कार्ड दीजिए, जिस तरह से शहर में आप राशन कार्ड देते हैं उसी तरह से गांवों में भी दीजिए यह भी पब्लिश होना चाहिए कि डीलर ने कौन कौन सा सामान उठाया है, कौन कौन सा नहीं उठाया है, बिक्री नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, अगर लोगों को नहीं दिया तो कहां बेचा । इसके लिए कानून में सजा की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि बढ़ती हुई मंहगाई रुक सके और हमारा मुल्क तरक्की कर सके । इन शब्दों के साथ मैं सरकार को बधाई देता हूं कि सरकार इनफ्लेशन का मुकाबला कर रही है और साथ साथ होलसेल प्राइस इंडेक्स भी कम हुआ है । ।धन्यवाद।

†[شری رفیق عالم (بہار) : - مہودیہ -

اسمیں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی بڑھی ہے - ایک مثال ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی اور مہنگائی بڑھتی گئی جوں جوں سرکار نے اسکو کم کرنے کی کوشش کی - اسکا کیا کارن ہے اسکی تفصیل میں میں نہیں جاؤنگا لیکن یہ بات ہے - اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مہنگائی نہیں بڑھی ہے - مجھے اپنے گاؤں جانے کا موقع ملا - مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو گاؤں کی حالت ہے وہ بہت خراب ہو رہی ہے چینی تو لوگوں کو ملتی نہیں ہے - سب سے بڑی مشکل تو یہ ہو گئی ہے کہ ڈسٹری بیوشن سسٹم ٹھیک نہیں چل رہا ہے - سمگلر انسپکٹر موٹر سائیکل پر چلتے ہیں اور اس سے اوپر جو اے - ڈی - او ہے وہ کار پر چلتے ہیں - کہاں سے انکے پاس اتنا پیسہ آتا ہے - جبتک بزنس مین اور ہمارے ان افسروں کی ملی بھگت رہے گی پرائس کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے - کچھ لوگوں نے وہاں کہا کہ جو ڈیلر ہیں وہ راشن دوکان پر آتے ہی نہیں ہیں - نا چینی لاتے ہیں - نا تیل لاتے ہیں وہیں اسکو اسٹاکسٹ کو بیچ دیتے ہیں - نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ راشن کی چیزیں بازار میں اونچے بھاؤ سے بکتی ہیں - میں اس سلسلے میں سرکار سے کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار ہمت سے کام لے تاکہ یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے یہ گھٹے - آج میں یہاں خود گیا تھا لنچ لینے کھانے سوچتا تھا کہ دس روپیہ میں مل جائیگا - لیکن لنچ کے ۱۰ روپیہ لے لئے - اگر مہنگائی گھٹی ہے تو اسکو ۵ روپیہ ہونا چاہئیے - اس پر بھی کنٹرول ہونا چاہئیے - ۲۰ روپیہ میں ایک ایم - پی - کس طرح سے کھا سکتا ہے .... (مداخلت) ....
آج جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں کارخانوں میں بنتی ہیں انکی قیمت بڑھتی جاتی ہیں لیکن جو چیزیں کاشتکار پیدا کرتا ہے اسکے دام گھٹتے جا رہے ہیں-

†Translitaration in Arabic script.

[شری رفیق عالم]

میں اس علاقہ سے آتا ہوں جہاں جوٹ پیدا ہوتا ہے - پچھلے سال ۴۰۰ روپیہ من جوٹ بکا تھا - اسوقت بھی کسانوں نے جوٹ لگایا اور ایک من جوٹ پیدا کرنے میں کسان ۱۵۰-۱۷۵ روپیہ خرچ کرتا ہے لیکن اس سال اسکا بھاؤ ۹۰ روپیہ من تھا - نتیجہ یہ ہوا کہ جوٹ جلایا گیا - جو گولڈن فائبر کہلاتا ہے اسکی یہ حالت ہے - جو فارن ایکسچینج ارنر کہلاتا ہے اسکی یہ حالت ہے اس کارن سے کاشتکار بہت بری طرح سے پریشان ہیں - ہمارے یہاں پورنیہ - دربھنگہ آدی جگہوں پر کاشتکار تباہ ہو گئے ہیں - برباد ہو گئے ہیں - کاشتکاروں کو انکی چیزوں کی قیمت ٹھیک نہیں مل رہی ہے - ہمارے دیش میں ۸۰ فیصد کاشتکار رہتے ہیں اگر انکی آمدنی گھٹ جائیگی تو ہمارے ملیں بھی بند ہو جائینگی ہمارے کارخانے بند ہو جائینگے - اسلئے سرکار کو اس بات کی طرف دھیان دینا چاہئے اور انکی چیزوں کی قیمتوں میں اتنا مارجن اوشیہ رکھیں تاکہ اسکو بھی کچھ منافع ہو سکے - کاشتکاروں نے جو بلیدان اس ملک کو دیا ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے - ۱۹۴۳ میں جب ہندوستان ایک تھا نہ پاکستان تھا نہ بنگلہ دیش تھا - اسوقت ہندوستان کی آبادی لگ بھگ ۴۰ کروڑ تھی - ۱۹۴۳ کے فیمن میں صرف بنگال میں دس کروڑ آدمی مر گئے تھے لیکن سرکار نے کوشش کی ہے اسمیں کوئی شک نہیں ہے اور جو بات حقیقت ہے اسے کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہونا چاہئے - لیکن اب ہمارے دیش

کی آبادی بڑھکر ۷۱ کروڑ ہو گئی ہے بڑھتی ہوئی آبادی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہے - پروڈکشن اور ری پروڈکشن یہ دونوں جب تک نہیں ہونگے ہم کتنا ہی پیدا کریں وہ کم ہے - اسلئے فیملی پلاننگ کے بارے میں ہمارے ورودھی دلوں کے لوگ کہہ رہے تھے - میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ۱۹۷۷ کا چناؤ ہوا تھا اسوقت کیا ہوا تھا - ۱۹۷۵ میں سرکار نے سوچا کہ لوگ کم بچہ ہی پیدا کریں لیکن فیملی پلاننگ جب تک نہیں ہوگا تو ہماری پیداوار اسکا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے - ملک کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے - اسی لئے سب سے پہلے ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنا چاہئے - میں اسلئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ۱۹۷۷ کے الکشن میں ہوا جنتا اس میں سہیوگ دینے کے ۱۹۷۷ کے الکشن میں کہا گیا کہ مظفر پور میں پانچ ہزار لوگ بندھیا کرن کے کارن مر گئے اور یہ کہا گیا مظفر پور میں کہ مظفر پور میں نہیں پورنیہ میں مارے گئے - پورنیہ کی بات سہرسہ میں کہی گئی - اور سہرسہ کی بات کسی دوسرے شہر میں کہی گئی - اسطرح سے افواہیں پھیلا کر لوگوں کو اندھکار میں ڈالا گیا جسکا رزلٹ ۱۹۷۷ میں آپ سب نے دیکھا - سرکار نے کوئی کام اچھی نیت سے کیا لیکن اسوقت ایڈکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے سوچا جائے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے - اسی لئے جہاں ملک کا سوال ہے - لوگوں کا سوال ہے - وہ ہم سبکو ایک ہونا ہے - چاہے وہ کسی پارٹی سے کسی جاتی سے کسی دھرم سے

تعلق رکھتا ہو - سبکو یہ سوچنا ہے کہ اگر ملک بچے گا تو ہم بچیں گے - ملک نہیں بچیگا تو ہم نہیں بچینگے - اسلئے ابھی جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اسکو منتری جی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں - ابھی میں آپکو دلی کی بات بتانا چاہتا ہوں - کل میں نے اپنے نوکر کو فیر پرائس شاپ پر بھیجا تین دن سے واپس آ رہا ہے کہ صاحب چینی نہیں ملی اب اگر دلی میں یہ حال ہو تو بتائیے گاؤں کا کیا حال ہوگا - ہمارا جو ایف - سی - آئی - ہے یہ وہائٹ ایلیفینٹ ہے اسکو کنٹرول کیجئے نہیں تو یہ سبکو بھوکھا مار دے گا -

دوسری بات یہ ہے کہ لوور طبقے کو آپ کارڈ دیجئے جسطرح سے شہر میں آپ راشن کارڈ دیتے ہیں اسیطرح سے گاؤں میں بھی دیجئے یہ بھی پھلش ہونا چاہئے کہ ڈیلر نے کونسا سامان اٹھایا ہے اور کون کونسا نہیں اٹھایا ہے - بکری نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی - اگر لوگوں کو نہیں دیا تو کہاں بیچا - اس کے لئے

PROF. C. LAKSHMANNA (Andhra Pradesh): Madam Vice-Chairman, the statement given by the Minister indeed makes one stand up and think about the whole thing.

The Minister has claimed that during the last 13 weeks the wholesale

انفلیشن کا مقابلہ کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہولسیل پرائس انڈیکس بھی کم ہوا ہے - دھنیہ واد -]

price index has moved down by 2 per cent. But then in the write up which has been given about the wholesale price index itself for the week ending 12th October, 1985, it has been recorded that there has been a rise in varying proportions in the wholesale price index as is evident from the document produced by the office of the Economic Adviser himself.

Secondly, if we go into the various wholesale price indices as provided by the monthly abstract of statistics, which has come to the library only a week or ten days back and which gives information up to the end of June we get a disturbing picture.

If we look at it for all the food-grains, the price index in March was 341.9 and it has gone up by June to 355.9. And for the careals, from 243.1, it has gone to 251.1. Pulses is the only item where there has been a slight decrease which is being claimed as applicable for the entire wholesale price index by the Minister. Then for the whole sub-group it has gone up from 275.92 to 282 and for the whole group including fruits, vegetables, milk products, eggs, fish, meat, condiments and other food articles all put together, it has gone up from 297.3 to 317.1. I do not want to go into details about the non-food articles, minerals and so, on and so forth. I see before me that in each of the items if we compare between March and June, as given in this Abstract, there has been an increase in every possible way.

Then I will be failing in my duty if I do hot point out its impact for the industrial workers and for the agricultural workers. For the industrial workers also, the all-India wholesale price index was 600 in the month of March and it has gone up to 624 in the month of June. This is about food. About clothing, it is evident that it has gone from 600 to 617 in June. If we put all the things together from 586 it has gone up to 606.

Then you have got information about different centres in the coun-

try, like Guntur, Hyderabad, Digboi and so on and so forth. And as I am persuing through, I find in each ol these places, the wholesale price index for industrial workers has gone up and at the same time the Minister claims that there has been a fall by 2 per cent. It is upto the Minister to kindly look into, the figures as provided by an official agency.

Then about the agricultural labourers, for food it was 588 in the month of March. Now it is also 583 in June. And in "general" it was 517 in March and it has gone up to 540 in June. And if we add to that what has been given as a rise of even point something in the case of wholesale price index, as given for the month of October, I see no reason how the Minister could come to a conclusion that the wholesale price index as a whole has gone down by 2 per cent. It is for him to look into it because r • knows better as he has got greater access to facts than we can afford to have.

Then coming to the weaker and vulnerable sections, what I find is that the Government thinks about the weaker and vulnerable sections in fits and starts. Suddenly there were stocks of wheat and therefore weaker sec tions conue to mind. But then the stocks are not enough to meet the re quirements of all the weaker sections. Therefore, the programme has been confined only to tribal areas. I would like to ask, if the tribal areas and the people living in the tribal areas deserve price support in terms of wheat or rice, as announced by the Finance Minister yesterday, why not the other people, the rural poor, urban poor, who are no better perhaps than the tribal poor? Why should these programmes not be thought for these people also? Why don't they think in terms of having a uniform programme for everybody who is below the poverty line, who is earning less than Rs. 6400, estimated by the Planning Commission as the poverty line? For that there is no answer. I While we talk about weaker sections, we talk about weaker sections of convenient points of convenient level, of convenient sector, or convenient categories and not weaker sections as a whole. Therefore the Minister may do well to look into this. Then, coming to the problemi of sugar and sugar-cane, the Minister has been very kind to the cane-growers. The Finance Minister and the Supplies Minister thought it fit to raise the price of sugarcane from Rs. 16.50 to Rs. 17 per quintal at 8.5 per cent recovery level. If that is the case, if there has been an in- 4 crease of 50 paise per quintal for the farmer, what is the sugar baron, the sugar lobby, getting? Their price has been raised by 40 paise per kilo. And then, another anomaly: This increase in sugarcane price is applicable for the season 1986-87 whereas the rise in the price of sugar is with effect from 1st of December, 1985. What does it mean? I would not like to accuse the ruling Congress or any party that they have taken any money as party, funds. Some hon. Members are objecting to that. I will not do that. But what is the lacuna there? What is the catch there? Why is it that the price of sugar has beerT raised by 40 paise per kilo and made effective from 1st of December whereas the poor farmer is being given the rise in the price by 50 paise only per quintal from the year 1986-87? It is for everybody to think about it: I will not accuse anybody.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRI_ MATI) SAROJINI MAHISHI]: I would request the hon. Member to conclude now.

SHRI KALPNATH RAI (Uttar Pradesh): I want to know this point.

PROF. C. LAKSHMANNA: I am not giving here what .has been written in Organiser or same other journal but those journals have clearly stated that a particular Minister was interested in giving boost to the sugar industry

and therefore he got delayed the import of sugar and so on. I will not even accuse him of it but this is what a paper has said. Therefore by drawing inferences from such news stories which have emanated it is possible, it is plausible and it is perhaps due to the manipulation of whosover it is responsible for the rise in the price of sugar and not so comparable a rise in the price of sugarcane.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: I would request the hon. Member to conclude now.

PROF. C. LAKSHMANNA: Madam, I will try to conclude as soon as possible.

Then the -whole problem is, if there has been a comparative control over inflation as claimed by the Minister, at the same "time, if we go to any market, any mandi in Delhi, any mandi in Hyderabad, any mandi in Agra or any mandi in Lucknow—these are the places where I have personally gone—and if we inquire from the fruit and vegetable sellers, if we inquire from the kirana merchants and if we inquire from the housewives.—I think all the honourable lady Members here should be more perturbed over what has been happening in the price structure—we invariably get the feeling, we invariably get the impression, we invariably get the picture from them that the prices have been going up as far as essential commodities are concerned, as far as the commodities which have accounted for to a 30 point share in the wholesale price index are concerned. If that is the case, it is all the more dangerous.

While there nas been a curb on the inflation, as claimed by the Government if there is no curb on the price rise of the consumption articles, it will become more problematic because it will affect the common mar*—and it will affect that man for whom all of us have been struggling, to raise his level of living, to improve his living conditions, to uplift him from the poverty line and so forth—and he will never be uplifted and he will continue to be where he is.

THE VICEiCHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: May I request you kindly to conclude?

PROF. C. LAKSHMANNA: Finally, I wo,uld only like to make a correction. While an hon. Member here was speaking, another hon. Member from that side, Mr. Rameshwar Thakur, said that the Plan document has been earlier discussed in the House. I would like to make a correction to that because I wrote a letter to the Deputy Chairman of the Planning Commission demanding that the Plan document be made public so that it can be discussed. I have got a reply from him; stating that as per the existing conventions and the proprieties as imposed upoiu the Planning Commission, the document cannot be made available to anybody unless it is discussed by the National Development Council.

Therefore, the Seventh Plan document came for any time of discussion only before the National Development Council and that too it is for as much as Rs. 1,80,000 crores which is the Plan outlay, But a Plan which is having as much as Rs. 1,80,000 crores was discussed and disposed of in two days time and that too by the Chief Ministers, Ministers and a few bureaucrats perhaps. But to say that it has been discussed thoroughly by the country is putting the facts out of focus. On the other hand, even till today the country does not know what the allocations are under different items because the Seventh Plan document is not available to us for the simple reason that the Hindi version of the Plan document is under print and that therefore the document can be distributed even to the Members of Parliament only when that is completed. Therefore, it is not proper that an important document of this nature is not placed before Parlia-

ment for discussion and the wisdom of this House and the other House has not been made available for understanding the Plan document.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: Now I request you to conclude.

PROF. C. LAKSHMANNA: And when once the document comes, it comes as a *fait accompli.* A Member may say or the Government may say that this has been the practice all through with all the Plans. But the Prime Minister once said, "I have been one who has been, breaking all traditions, if necessary." Here is one important point that where the Prime Minister and the Government can break the tradition of not making available the document to Parliament and other organisations before it was placed before the NDC. A wider discussion on the Plan document would have corrected some of the things that are there in the Plan document as we understand from the information that we have seen.

The rise in prices of the essential commodities is intimately linked with the planning process. The planning process will become meaningful only if there i_s enough of opportunity for the highest forum in the country and other bodies to have a look at it and discuss it so that its impact can be discussed properly. In that light, I would request the Minister once again to look at his own statement, to, look at the facts that are available to him more than anybody else in this House and to have the correct perspective of the state of affairs in regard to the essential commodities prices today and make necessary correction to, it.

Thank you.

- THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: Mr. Bhandare. I request you to conclude in seven minutes.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE (Maharashtra): The debate which has preceded has gone *on* a very general and vague $term_s$ which really lends assurance to the general feeling that the Government is trying to do all it can to control the situation.

But that really is not the crux of the matter because what I find is that in whichever way you look at it, inflation- is the cruelest form of taxation, particularly on the poorest of our population, and if it can be avoided, the Government should do all within its means to see that the impact of this cruelest form of taxation on the poorest people of our population is minimal.

Unfortunately, it does not happen. We had expected high inflation. Several economic experts said that this was a high inflationary Budget. I also said it at that time here particularly because you administer prices, you suddenly increased the rail tariff for passengers and goods, you increased the price of crude oil. That means a major cost of transport, which leads again to increase in the cost of the goods. The multiplier effect is tremendous.

But I must confess here that I have been proved somewhat in the wrong. The budget has really not proved as inflationary, Many said that it would be at least 15 per cerff: I Tiad also a feeling that it would get a double digit, but it has remained very, very much under that figure. It is factually correct that the rate of inflation has been the lowest in seven years and half of that was at the end of the last year. But we must realise that we live in a world and the world ha_s its own inflationary effect on India as well as other countries. I have only to read the several certificates which this country has got saying that among the developing nations, this is the best country which has managed its inflation. So, let us, therefore, start doing what we mean to do.

Now, I come to the other part of the matter, namely, that what is being done is not enough and much re-

mains to be done. Because it is one thing fo say that the wholesale price index is kept under control and that it does take time for the wholesale price index to percolate and the impact of its reduction being felt on the retail prices. What is o,f utmost importance is the present retails prices. That is where it affects the common man. I think the Government should do well, as has been pointed out by many Members of" my party today, particularly my estimated friend, Shri Rafique Alam, that we should not push the rise in retail prices under the carpet at all. We should be very realistic about it and try to see how we combat it. It is something which is predictable, because prices of rice and wheat have gone down, and prices of sugar and edible oils have suddenly shot up. The price of jute has completely stumbled. This is something which can be foreseen for some time in advance. So far as shortage of sugar is concerned there is over 24 lakh tonnes deficit in production. The rise in prices was on the cards that the prices would rise.

I would like to repeat what I have said in this House again and again, that unless you have an effective public distribution system, there is no manner in which all your fiscal policies and all your other polices will really bring the desired end of controlling the retail prices. I think that the Government should declare a war on that front then they will be able to tackle this public distribution system effectively. I do not see why people in all centres are not involved in the public distribution system. Why there should not be a centre in every locality where your van which is selling goods through fair-price shops eoes; and the goods should be distributed by the people of that locality, of course, through the agencies of the oeoDle who are managing that van. On the other hand, the peoples particirjation is nil. They do not know from where to get the coconut oil. They do not know from where to get the groundnut oil. The Minister is energetic, active and very effective In fact, when I look at him, I also get .. ..

SHRI V. GOPALSAMY: Dynamic.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Yes, as dynamic as my friend here. But the point is that he must pay urgent attention to this aspect. I can tell you in Switzerland there are two cooperatives'—(i) Migros? and (ii) Cops?. They have, succeeded to such an extent that they have driven out multi-nationals from the market in that country. If that can happen in Switzerland, I see no, reason why it cannot happen with greater effect in our country.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra): In Maharashtra also . . .

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: In Maharashtra the achievement is big. Madam, something must be done. Because of this policy the agriculturists are at the receiving end. When the prices rise he does not get commensurate with the rise. When the prices stumble he gets even less and less than the market price. That thing must be changed.

I am constrained to point out that the performance of the Food Corporation of India is really dismal and poor.

In fact, when I went to Maharashtra, somebody mentioned it to mer-you call it Food Corporation of India we call it Food Corruption of India, And it is true because I know that my Government is not interested in shielding inefficient and corrupt officials These FCI officers are mixed with mandiwalas. I have attended a came in Nagpur District. They were tellinE me when they bring their cotton tc the Mandi, the man says: we will have to get this cotton tested from the headquarters and it will take 15 davs So, you come after fifteen days. Ther we will see whether your cotton is ur.

Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare

to the mark or sub-standard—with the result that the farmer cannot wait there for fifteen days and if the market price is Rs. 250/-, he sells it at Rs. 220/- and he goes back to his village. I think this is very, very serious matter.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: You are talking about the Cotton Corporation of India or the Maharashtra Cotton Corporation?

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: I do not know. If I am wrong, I am wrong. But I am conveying the complaints and those complaints are genuine.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: So far as the cotton monopoly procurement programme is concerned, such things are not there. The Cotton Corporation of India may be doing such things.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: All right. I was only telling that the agriculturists are not getting the remunerative prices for their produce. Whether it is Cotton Corporation of India or some other body, here, the great fraud has to be exposed.

THE VICE-CHAIRMAN DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: C request the hon'ble member to conclude.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: So, what I am saying is that steps must be taken. Ultimately, there are three pillars— he basic things are to which our Government is pledged. It shall re-nain pledged for all times and that is, irstly food. The first pillar i^ of bod—that every person in our coun-ry will get food and it is a matter if pride, now we have provided food or everyone. Please remember that he expojt market for food products 5 extx'et ely limited. It is shrinking so fast. We are producing 150 million tonnes whereas China is producing 400 million tonnes. The second pillar is work, work for everyone and third productivity, so we usher in an era of plenty. I want to insist that the Hon'ble Minister gives top priority to these three pillars on which our policy should be based, namely, there should be work for everyone, there should be food for everyone. Unless that is there, we cannot become self-reliant. The third one which I want to say is the question of productivity. Therefore, food, work and productivity should be the main thrust, with this, I will say, you are proceeding in the right direction of strengthening the anti poverty programmes, food-for-work programme, the integrated rural development programme, the rural employment programme. Let the Government come with a big policy for fighting the poverty in a big way. If that is done, I *czz* no reason why for every year, we will nave to discuss this with the usual ritual of the problem of rising prices. Thank you.

DR. SHYAM SUNDAR MOHAPATRA (Orissa): Madam Vice-Chair-man, while discussing price rise, I can submdt to you—whether it is price rise, whether it is corruption, whether it is smuggling, these are all concomitants of economic ills the country is facing todpv because the country has no philosophy of 'Is own. Look at the USSR. Whether it was the time of Stalin, Malenkov, Khruschev, Bulga-nin, Breznev, Andropov or Gorbachov, the price structure remains as of 1950s. In China, what I saw—whether it was Mao Tse-Tung, Chou En-lai or it was Lin Peo or the Gang of Four or the present day Xio Ziang, the price structure remains of 1950.

I was astonished yesterday when I was with the Vice-President of India in his roomi and when this discussion came—we were very happy that it was coming.—the hon. Minister said there, "No, our price structure is that of 1946." Well, if you go to purchase

ghee in the Parliament House—you know I was here an MP in 1971—it was Rs. 10 a kilo in 1971 and today it is about Rs. 50. Similarly there are various other' items. The price structure has gone up like anything, at least lour times.

Madam, according to newspaper reports, as my friend Mr. Bhandare said, inflation has gone down; it is hardly 4.4 per cent now. In the corresponding period last year, it was 7.7 per cent. *I* can tell you, this is absolutely a jugglery of statistics which the economists are doing. Inflation has gone up. Ask the housewife. They buy meat in Calcutta at Rs. 40 or Rs. 50. The price of every household item has gone up. Kaddu is four rupees a kilo; brinjal five rupees. The price of edible oils has gone up. In Delhi the price of milk has gone up. Tomato is ten rupees a kilo; Parrroal ten rupees. Who can afford these prices? But you may say that the country is facing no inflation, that 4*4 per cent is nothing. « In Japan, it is 1.3 per cent; so 4.4 per cent is no inflation at all. I would submit that this is all a jugglery of figures. Madam, the Press Secretary of Lyndon B. Johnson who was President of the United States said—I am quoting:

"Whenever Pravda extols the nutritional value of cabbage . . ,"

This is for my CPI(M) friends.

" . . .there is wheat failure."

So, whenever our Government says that inflation is controlled, you must be aware, Madam, that the price rise is rampant. What I want to suggest to you is that nobody is worried about > the inflation. The question is, how do we face it? In Latin America, particularly in Argentina it is 400 per cent inflation. In Bolivia it is 320 per cent. ' In El Salvador it is nearly 500 per j cent. In Guatemala it is 600 per cent. In Africa, it is 40 per cent. Whether it is Zambia or Zimbabwe or Sudan, the inflation is 40 per cent. We ere not - worried about it. The question is how you are going to arrest the price rise. As Mr. Bhandare rightly said, it is a question of the means of distribution and the means of production. Who is going to control the means of distribution—me or the Congress Party or the Government from the BDO, Tehsildar to the Collector, the Under Secretary, the Deputy Secretary, the Joint Secretary and the Secretary who are at the helm of affairs? They are to control it, not me, not the poor people, not the housewives. The distribution system is corrupt, bankrupt. There is no distribution system at all because we depend on the bureaucracy who have nothing to do with the people. We have everything to do with the people, but the bureaucrats have nothing to do with the people. That is why I must urge on the Government to control the means of distribution.

Madam, what is the purchasing power of the rupee today? Lohia long back had said that the value of the rupee had gone down to three annas. I can quote the figures. In 1986, it was 66 paise; in 1971, 52 paise; in 1978, 30 paise; in 1980, 25 paise; and today in 1985, it is only 15 paise. So the purchasing power of the rupee has gone down. Our Prime Minister, a very dynamic young Prime Minister, is going to give rice and wheat at subsidised rates to tribals, Harijans and backward people. Very good. The Minister Mr. Singh Deo is here. I say, this is because you are not able to sell your wheat anywhere in the world and it is going to be absolutely stale *in* your godowns. After you have issued OGL licences to all people, neither Oman nor Kuwait nor Bahrain nor the USSR, nobody, is going to buy it. You do not know what to do with the wheat. So you say, let us give it to the poor people, Harijans, tribal and the backward people. Therefore, it is under compulsion that you are doing it. I say, we must give it to them at subsidised rates. If China can do it, if Russia can do it, if Yugo-

[Dr. Shyam Sundar Mohapatra] slav, Czechoslovakia, Hungary and Bulgaria are giving it at subsidised rates, at the prices of the 'fifties, why can't we do it?

Madairn, black money is again a concomitant of this economic ill.

What is the black money in circulation today? More than Rs. 70,000 crores. Kaldar estimated it at Es. 606 crores in 1953. Wanchoo put it at Hs. 1400 crores in 1970. Rangnekar said Rs. 21,000 crores. Gupta & Gupta have recently said Rs. 70,000 crores. I am quoting facts, I am not quoting fiction. If this is the situation how are you going to arrest black money? By arresting the Managing Director of R. K. and putting him behind the bars you cannot stop it. What is happening in Reliance? You arrest somebody as it suits you. No. If there is a policy, any black marketeer, any racketeer, any smuggler, any hoarder who is doing a social crime, should be arrested and put behind the bars. That is the philosophy you have to project in right earnest to the people. Then only the people will believe you. I know in Bombay all smugglers and black marketeers have sat with the President of India or are sitting with Ministers to project their image. If this is what is happening, how do you expect them to serve the country's interests? It is not possible. The International Monetary Fund's staff made a survey of the economy of India. They are highly pleased with the way the Indian economy is going; they are highly pleased. They say: "The quantum of unaccounted for income and wealth in the country today is 50 per cent of the GNP." That means, if our GNP today is Rs. 1,45, 145 crores, it means the unaccounted for money today is Rs. 72,000 crores. This is what the report of the International Moratory Fund's staff says. With this you cannot expect that the country's economy will be under an egalitarian philosophy or sociaLst philosophy to which we are commited. According to the Constitution it is a socialist country. Madam, I conclude my spe- I ech with these words that a country which has no basic economic philosophy of its own, a country which entirely depends on the bureaucratic set up and on their working habits, a country which cannot control the hoarders, the blackmarketeers, the racketeers and is giving them freedom at will because they serve the interests of political parties—1 don't say 'party' —such a country's economic development is impossible. You cannot arrest the price rise, you cannot arrest anything. You have an open door to all blackmarketeers. Thank you.

SHRI V. NARAYANASWAMY (Pondicherry): Madam, the issue before the House is the rising prices. How to control the rising prices is the point for consideration here. In these days we say in our . country that we were not geltmg sufficient foodgrains. Now, after the Plans we have seen that our country not only satisfied our needs, it is exporting foodgrains to other nations. In the industrial field also our country has developed a lot. In spite of these facts we find that hoarders, blackmarketeers, middlemen and smugglers are coming out with flying colours. We see agriculturists shedding their sweat and toil and making a good harvest. But when the agriculturist comes to the market, there middlemen are playing a major role. After a long time the agriculturist comes to the market where the middleman, within ten to fifteen minutes, earns a lot of money between the ag riculturists and the trader and, therefore, the agricultural prices have gone up. Not only that. The hoarders and I blackmarketeers find it very pleasant • for them to earn and amass wealth. I Now the Government is taking strin?-j ent action against them with a view J to arresting the price rise. In soite of it, those people are holding the mar-I ket and people at large to ransom in

several aspects. The poor Government servants, the agriculturists, agricultural labourers and other people who are in the lower strata of the society are finding it very difficult to cope up with the price rise. That being the position now we have to find out ways and means of arresting the price rise. For that, Madam, my suggestions are these: The public distribution system should be widened so as to cover the entire country and it should reach even the remote corner of our country to reach the common man in order to satisfy his needs. Not only that. The schedule of essential commodities should be expanded to include more items taking into consideration the needs of the people for consumer goods to enable them to buy these commodities at cheaper rates. Further, we should also see that there are uniform prices for the essential commodities throughout the country so that everybody buys them at the same rates. Not only that. The Government should make strenuous efforts to arrest the price rise by making the provisions of law more stringent and by putting behind the bars persons who are mainly responsible for the price rise.

With these words, Madam, I conclude my speech and thank you.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: Now, Mr. Dhabe. I would request you to take only five minutes.

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): How is it possible? I do not understand this. It is a four-hour discussion and our Party gets about fifteen minutes. So, you cannot say that I should take only five minutes.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: All right.

SHRI S. W. DHABE: You have given more time to some Members because they are in the ruling party.

Madam, the statement made by the Minister shows that the Wholesale Price Index has moved down by 2 per cent and he also admits in the statement that the prices of essential commodities have moved up. I have got a statement before me showing that the prices of all essential commodities have gone up. Therefore, I do not understand what he wants to say. The wholesale prices of vegetables and fruits have gone up by 20.3 per cent; the prices of eggs, fish and meat have increased by 16.4 per cent; the prices of sugar and khandsari have risen by about 19 per cent; and the prices of cereals, which are the major items of consumption in the country, have also gone up by 15 per cent. This is apart from the increase in the prices of coal, petrol and other things whose prices have gone up. Therefore, to say that the prices of only some commodities have gone up is not giving the picture correctly. Therefore, I agree with my friend who spoke just now, Mr. Mohapatra, that it is a folly to say that inflation has come down and it is only 4 per cent. The real test is in what the common man feels and whether he has to pay more. It is just like saying, as we say in labour matters, "rationalisation without tears", "price rise without tears". Probably the Minister wants to believe that there is price rise without tears in the eyes of the housewives. Prices are going up. The Indication is very clear. The clear indication is that the Government is paying more Dearness Allowance to its employees.

Madam. I was surprised to find from the Report of the Labour Ministry, 1984-85, wherein they have given a chart, that the Consumer Price Index has gone up and also the Wholesale Price Index has moved up. There is the Working Class Consumer Price Index for food and other commodities. In 1981, it was 465. In 1982 it was 498. In February 1983 it was 564. In December 1983 it was 591, and in December 1984 it was 610. The wholesale index is also similar. In

[Shri S. W. Dhabel December 1984 it was 611. In 1983 it was 577. The index itself belies . . . *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: The hon. Member should address the Chair, and he should kindly continue.

SHRI S. W. DHABE: He is addressing me. What can I do?

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: You please continue.

SHRI S. W. DHABE: Whether the rgures are correct or not. Government servants are paid more dearness allowance and the cost is related to the cost of living index. Therefore, the talk of growth and stability in prices is a humbug. With this mixed economy and the budgetary system which the Government is following, it is not possible to rationalise the the price structure nor to control the prices. It was stated that Russia and China have got stable prices during . the last 50 years. But the system is different. And, therefore, in our system of mixed economy and with deficit budgets, though the hon. Minister had claimed that there is no price rise, in spite of the assurance prices are going up. The only solution is to give relief to the poor people by a proper agency.

Now. the increase in prices of essential commodities has not percolated also to the cultivators. On the one hand, the Government has proclaimed that it wants to give remunerative price to cultivators, on the other, this policy is not followed. They are caring more for the sugar industry barons and the middlemen or the dalals than the real cultivators. The evidence is that in Kerala, coconut which was priced at Rs. 4, is now sold at Re. 1. Government is importing not only coconut oil but also copra. And a large number of people, 13000 people of Kerala Congress staged an *ancktlan.* It is gonig on in Kerala. On account of the wrong policies of the Government of import and export of coconut oil and copra the cultivators in Kerala are suffering. Therefore, it is linked up with Government policy of export and import. If the Government wants to pay remunerative prices to the cultivators, they must radically change the export and import policy; it should not be at the cost of cane-growers or manufacturers of sugar.

Last time we discussed about sugar. While the consumer had to pay Rs. 4 to Rs. 5. the Government is bringing ' it here at Rs. 1.60. And the Minister had to admit here—the previous Minister.-that cent per cent levy is there on the sugar so that we want to have more prices and make profiteering at the Government level. Therefore, the question involved is not merely to have public distribution system but also proper quality in respect of import and export of essential commodities like sugar, wheat and also rice. I am told—my friend was just now referring to wheat—that wheat exported was sub-standard. I would like to know from the Minister whether sub-standard wheat was exported and it was rejected by some countries. If that is so, it is a very serious matter. Quality control is very essential for the export of any commodity. The Government has given a statement here that they will have a Civil Sup-, plies Corporation so that adequate supplies are available in each State.

4 PM

I find no reference to it in the statement. But they have not been set up in all the States. It will go a long way if Civil Supply Corporations are set up in each State so that essential commodities are available. We find that in inaccessible areas of North-Eastern parts, especially the village areas, there is no proper distribution system. The ordinary vegetables cost Rs. 15/-per kilogram and the price of meat was about Rs. 50/- per kilogram'. Therefore, a public distribution sys-

tem is not necessary only for the urban areas. I would like to know what steps the Government has taken to extend the public distribution system to village and tribal areas, especially in the inaccessible areas of North-Eastern parts and other parts of the country.

There is one more suggestion and I am finishing. The Government has said in the statement that surveillance is being kept on the prices of essential commodities. It is a misleading statement. What steps are they taking? No steps are taken against those who are hoarders. Steps are not taken against the quality control Inspectors who authorise exports. The public distribution system is not being extended to the inaccessible areas. My suggestion to the Minister is that they must try to have an integrated policy for the commodities. Otherwise, there is no, other alternative except to pay dearness allowance to all the sections of the people. In this connection, the complaint of the Government Servants is that even today the price rise is so high that 100 percent neutralisation is not sufficient. They demand that in order to neutralise the cost of living, it should be 150 per cent. If that is so, the Government will not be in a position to pay. If the prices are not controlled properly, I think we are heading for a crisis. Therefore, I suggest that the very essential steps of setting * up corporation and setting up of public distribution system must be taken early. Also, a proper export-import policy is essential for having a check on prices in the country.

श्रीमती शान्ती पहाड़िया (राजस्थान) : महोदय, जिस विषय पर यह चर्चा हो रही है यह बहुत ही अहम विषय है। मंहगाई जो है, यह मंहगाई कहां से आई है, कैसे आई है, इसके भी कई कारण है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि जो हमारे किसान भाई हैं, वे एक भेड़ चाल चलते हैं, सारी मेरे को यह कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वे एक भेड चाल चलते है। जो एक ने बो दिया, दूसरे ने भी वही बो दिया, वह भी वही पैदा करेगा। क्योंकि जिस वक्त गन्ना ज्यादा होता है तो गन्ना ज्यादा होने के कारण सूगर सस्ती होगी, गुड़ सस्ता होगा, जैसे अभी एक भाई कह रहे थे कि जूट में आग लगानी पड़ी। महोदया, जूट में आग लगाने का यही कारण है कि जब ज्यादा पैदावार होती है तो वह चीज सस्ती हो जाती है और जब चीज नहीं बोई जाती है, उसकी उपज नहीं करते हैं वह मंहगी होती जाती है, चाहे दाल हो, चाहे तेल हो, चाहे गेहूं हो चाहे गन्ना हो, किसी चीज को भी ले लें, जब पैदा कम होती है तो वह चीज मंहगी होती जाती है। महोदया, मेरा यह सजेशन है कि मंत्री जी ऐसा करें कि जो बड़े-बड़े किसान हैं, छोटे किसानों के बारे में मैं नहीं कह रही हूं–जो बड़े-बड़े किसान हैं जिनके पास कई एकड़ जमीन है, उनको जिस तरह से हम अफीम की खेती कराते हैं, उनको भी नापतोल कर इस तरह से कहा जाए कि इतने में आप गन्ना पैदा करें, इतने में धान पैदा करें। अगर आप ऐसा करेंगे तब महंगाई भी कम हो सकती है और बहुत से लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आ सकते हैं। दूसरी बात इसी के साथ-साथ मैं यह कहूंगी कि कपड़ा भी महंगा है। कपड़ा भी खेती से पैदा होता है। कपास यदि ज्यादा होती है तो ज्यादा पैदावार होने के कारण सस्ती बिकती है और इसमें मिलें सस्ता कपड़ा दे सकती हैं जिससे गरीब लोगों को फायदा होता है। अगर कपास कम पैदा होती है तो महंगाई बढ़ जाती है कपड़ा महंगा तैयार होती है। यह जो मंहगाई चल रही है यह तब तक नहीं मिटेगी जब तक किसान लोगों या कम्पनी और इंडस्ट्रीज वाले लोगों पर यह कानून लागू नहीं किया जाएगा। तब तक न तो मंहगाई मिट सकती है और न लोग गरीबी की रेखा के ऊपर उठ सकते हैं। यह साथ-साथ चलें, मैं यह कहूंगी कि अनाज जो बोआ जाता है इसमें यह है कि पहले जौ होता था, चना होता था यह गांव में गरीब आदमी को सस्ता मिलता था। पहले यह होता था कि जो मेहमान आता था तो उसके लिये गेहूं की रोटी बना कर देते थे। अब तो जौ और चना बिलकुल

[श्रीमती शान्ती पहाड़िया]

खत्म होता जा रहा है। आजकल चने का जहां तक प्रश्न है हमारे गांव में तो यह हो गया है कि जिस घर में चने की रोटी बने वहां जाता हुआ मेहमान भी रुक जायेगा कि चने की रोटी बन रही है इसलिए खा कर के जाऊंगा। यह हाल चने का हो गया है। इसलिए मेरा कहना यह है कि सब किस्म के अनाजों की चाहे चना हो, दाल हो, गेहूं हो, चावल हो, जवार हो, सब को बराबर हिसाब से बोआ जाए। अगर तिलहन पैदा नहीं होगा तो तेल कहां से आएगा। तेल निकालने वाले बीजों की खेती भी की जाए। सरसों भी बोई जाए। हमारे यहां इस बार इतनी सरसों हुई है, अभी जो रबी की फसल गई है उसमें इतनी सरसों पैदा हुई है कि चार रुपए किलो तेल बिका है। इतनी सरसों हुई इसलिए तेल सस्ता हो गया। इस पर अगर सरकार रोकथाम नहीं करेगी तो ऐसे दाम ऊंचे नीचे होते रहेंगे, मंहगाई भी होगी चीजें सस्ती भी होंगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे-अच्छे कार्यक्रम चला रखे हैं। मैं सोचती हूं कि और भी अच्छे चलाएंगी तथा यह जो महंगाई बढ़ रही है इस पर ज्यादा ध्यान देंगे। इतना कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करती हूं।

SHRI V. RAMANATHAN (Tamil Nadu): Madam Vice-chairman, the hon. Minister has stated in his statement that the inflation is declining but the price rise is not falling to the same extent. He has further stated that the availability of essential commodities is generally satisfactory. But fifty per cent of population is living below the poverty line and there is no purchasing capacity among the masses. Therefore, while we may appear to be having a surplus of commodities, actually we are not in surplus. That is what I want to submit to the hon. Minister. Actually our requirements are much more but there is shortage of purchasing capacity among the people. Fifty per cent of the people are living below the poverty line. It may anrjear that we are surplus in production. For example, it was stated that we are producing 62 lakh tonnes of sugar. But in another ten or fifteen years our requirement will be one-third more than what we are consuming today. Are we planning to produce that much? Have we .prepared our plans to produce such a quantity within ten or fifteen years? We are having the potential to produce but we are prepared to purchase worth thousands of crores from abroad but we are not prepared to produce and manufacture sugar here when we have got the capacity to do *&o.* The sugar factories are now given a lot of benefits. Previously they were allowed to . sell only 35 per cent in the open market. Now it has risen to 45 per cent. Because of this, they are getting Rs. 225 crores per year. They must be made to modernise the mills. They are showing loss in production. That is because the industry is not modernised. If we can modernise the industry, we can improve, production and meet the sugar demand. The sugar factories are paying Rs. 16.5 per quintal to the growers which is linked *to 8.5* point recovery of sugarcane. Recently, a seminar was conducted by the factory owners to consider how to bring down the peak level recovery point. The Government is taking many steps to bring about new varieties of short duration crops but with high sugar content. If the peak period recovery is developed and sugarcane is crushed during the peak period, » there will be lot of production of sugar and it will give a higher recovery rate. But because the factory owners will have to pay higher amount to the growers if the recovery rate is hit?h, now they are trying *to* bring it down, and that is why, this seminar was held. Thev are only thinking on these lines. This attitude should be discouraged; this situation should be ' avoided, because national production is more imoortant and these people must be allowed to act in this manner in order to avoid higher payment to cane growers. Government is spending lakhs of runees in order to develop new and better varieties. These pro-

grammes should be properly implemented and the Government must see that only the developed varieties are cultivated.

We must also modernise our distribution system. We must modernise the transport system, as well. Unless we do it, rise in prices cannot be checked. For this purpose, the Government must appoint a high-powered committee to manage the price situation. They must also take care to see that all industries producing essential commodities, produce to their fullest capacity. Under-production should not be allowed and they must produce to their full capacity.

As I said earlier, modernisation of industry is very important. The prices of essential commodities like coal, steel, cement, food articles, vegetables etc. are going up. We have to keep the prices under control by adopting modern means. This can be an effective way to check prices.

Then wastage must be curbed. The industry shows less of production in their accounts so that fhey do not have to reveal higher profits. This is a problem which must be looked into seriously.

I submit that unless effective measures are taken, rise in prices cannot be avoided.

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभार मानता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर, जिस पर सारा दिन चर्चा रही, मुझे भी दो शब्द कहने का आपने अवसर दिया। महत्वपूर्ण तो इसी बात से सिद्ध होता है यह कि सारा दिन इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मंहगाई, अकाल, महामारी और युद्ध यह ऐसे प्रश्न हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न है। इस पर कोई राजनीतिक मुद्दे या राजनीतिक चर्चाएं बहुत जरूरी नहीं हैं। चाहे सरकार हो या विपक्ष हो, दोनों को खुले दिल से इन सवालों पर विचार करना चाहिए। सभी लोगों ने कहा है कि खेत और कारखानों में पैदावार बढ़ाई जाए, तो महंगाई कम होगी। यह बात अपनी जगह सत्य है। लेकिन उसकी वितरण व्यवस्था भी सही हो। यह स्थिति जरा दोषपूर्ण है। इस देश के किसान ने खेत की पैदावार बढा कर तो देश को आत्मनिर्भर कर दिया था, खाद्य-सामग्री में, खाने की चीजों में, चाहे अन्न हो, चाहे और चीजें हों। हमें याद है कि देश जब आजाद हुआ था तो क्या हाल था। इसके बाद भी 1965 में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री बनीं, तब भी क्या हाल था।

तो इस देश के किसान ने देश को आत्म-निर्भर कर दिया। अब बाहर से मंगाने के बजाय हम बाहर भी भेज रहे हैं बहुत सी खाद्य-सामग्री। जो चीनी वगैरह हम मंगा रहे हैं, शायद सस्ता रेट करने के लिए, वरना किसान को अगर उचित मदद दी जाए तो चीनी के मामले में भी हमको मंगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा ख्याल है।

कठिनाई यह हो जाती है और यह दुखद घटना भी है कि जो इस देश में पसीना बहाने वाला है, किसान और मजदूर जो पैदावार बढ़ाता है, उसको भी आंसू बहाने पड़ते हैं। यह नहीं होना चाहिए। पसीना बहाने वाले को अगर हम प्रोत्साहन देंगे, तो खेत और कारखानों की पैदावार और बढ़ जाएगी और यह मंहगाई वाला जो अभिशाप है इस देश के ऊपर, यह एक महामारी से भी बड़ा संकट है मंहगाई, वह खत्म हो सकता है और किसान या मजदूर को, खेत में काम करने वाले को हमें साधन और सम्मान दोनों चीजें देनी चाहिएं, और आदमी सम्मान के लिए भी काम करता है तथा साधन के लिए भी काम करता है। खेत के किसान और मजदूरों को साधन और सम्मान दोनों नहीं दिये जा रहे हैं। साधन और सम्मान अगर पैदावार करने वाले को दिये जाएं, तो पैदावार में और ज्यादा प्रोत्साहन होगा, पैदावार देश की और बढ़ाई जाएगी। पर उनको सम्मान की बजाए अनेक जगहों पर अपमानित होना पड़ता है।

[श्री राम चन्द्र विकल]

मैं किसान की बातें कहूं, चाहे लोन का सवाल हो, चाहे खाद का, चाहे बीज का सवाल हो, उनको कठिनाइयां भुगतनी पड़ती हैं। यही हाल गरीबों का भी है। पैदावार बढ़ाने के बाद वितरण व्यवस्था सही होनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं तो गांव का रहने वाला हूं गांव की ही मुझे बहुत सी घटनायें याद हैं। हमारे गांव की शादियों में पहले तांबे के पैसे के छोटे-छोटे टुकड़े होते थे, उनको बिखेर दिया करते थे बड़े लोग और जो गरीब लोग होते थे, वह धूल में से उनको चुगा करते थे शादी के मौके पर। उनमें भी कुछ होशियार लोग होते थे जो चार बांस लेते थे और उन पर कपड़ा बांध लेते थे और वह बिखेरी हुई मुट्ठी को ऊपर ही टांग लेते थे। बेचारे जिनके पास यह कपड़ा और बांस नहीं होता था, वह परेशान होकर आंख में धूल लेते थे, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था।

हमारी सरकार की नीयत अच्छी है, योजनाएं अच्छी हैं। अभी प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की है एक महीना पहले कि हम गरीबों में खादय-सामग्री बांटेंगे और उसका अमल भी हो रहा है—खाद्य-सामग्री गरीबों में बांटने की प्रधान मंत्री की घोषणा का सर्वत्र स्वागत किया गया है। लेकिन वहां तक पहुंचने में वह जो होशियार लोग हैं, जो चार बांस पर कपड़ा लगाए हुए हैं, वह कितना पंहुचने देंगे, यह विचारणीय प्रश्न है। होशियार लोगों से हमारे देश का गरीब त्रस्त है। हमारी योजनाओं का प्रारूप कितना अच्छा बनाया जाता है, पर नीचे जाते-जाते वह भी कुछ कमजोर पड़ जाती है। हमारी आर्थिक सहायता जो गरीबों को दी जाती है, वह भी नीचे जाते-जाते कमजोर पड़ जाती है। होना यह चाहिए कि जो योजना बनाई जाए, जिनके लिए बनाई गई है उन तक सही रूप में पंहुचे और योजना बनाने में भी उनका योगदान होना चाहिए। बहुत से लोगों ने अन्तर्राष्ट्रीय जगत की चर्चा की है और यह बात सच है मंहगाई की, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी हो गई है। चाहे युद्ध हो, चाहे मंहगाई हो, यह बाहरी देशों से भी संबंध रखते हैं। अगर अकाल पड़ेगा तो उसका हमारे यहां भी असर होगा। हमारे यहां अकाल पड़ेगा तो उसका दूसरी जगह भी असर होगा। पैदावार और अकाल का हर जगह असर पड़ता है। यह जो दूसरे देशों की चर्चाएं की गईं, कुछ देश हैं जो इस समस्या पर कन्ट्रोल कर पाए हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि हम कीमत मुकर्रर करते भी रहे हैं दूसरे देशों में बहुत कम की गई हैं, लेकिन जो मूल्य किसी चीज का निर्धारित होगा बाजार में वह उसी भाव पर मिलेगी, कम या ज्यादा नहीं मिल सकती। हमारे यहां सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, सस्ते बाजार हैं, चाहे कोई चीज हो सस्ती कीमत पर जो लिखा जाता है वह भी सही नहीं मिलता है। यह भी सच है, मूल्य भी निर्धारित कर दें और तब भी सही नहीं मिले और उसमें भी गड़बड़ हो जाए तो यह बड़े दुख की बात है। इस सरकार की जो नीति है सस्ती दुकानें खुलवाने की, सस्ते मार्कीट बनवाने की उसका भी उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है। दूसरे बाजारों में दामों पर कोई नियन्त्रण नहीं है जितना चाहे कोई दाम ले ले, जिस कीमत पर चाहे बेच दे, उस पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। उपसभाध्यक्ष महोदय, तीन चीजें अत्यावश्यक हैं, भोजन, वस्त्र और दवाएं। ये चीजें तो कम से कम सस्ती गरीब लोगों को मिलनी चाहिएं। अगर ये चीजें सस्ते दामों पर गरीब जनता को मिलती हैं तो मैं समझता हूं कि इसके अन्दर सब से बड़ा समाजवाद छिपा हुआ है। जो कठिनाइयां गरीबों को हैं उनकी मैं ज्यादा चर्चा यहां नहीं करना चाहता। अकाल हो, अतिवर्षा हो और चाहे सूखा हो, मेरे देश में प्रवृत्ति यह रही है, कि जिसमें मैं समाज को भी दोषी कहने को तैयार हूं, हमारे यहां मजबूरी से फायदा या मुनाफा कमाने की आदत है। अकाल पड़ गया तो व्यापारी समझता है कि अब तो मंहगा होगा ही होगा। हालांकि ऐसे मौके पर तो चीजों का उदारता से वितरण होना चाहिए। लेकिन व्यापारी कहेगा कि अब तो अकाल पड़ गया है, कई राज्यों में सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, समुद्री तूफान आ गया इसलिए अब मुनाफा अच्छा मिलेगा। इसको व्यापारी अच्छी तरह से समझता है। मेरे

सिकन्दराबाद के एक व्यापारी सुबह ही सुबह फोन मिला कर पूछा करते थे, कभी मद्रास, कभी कलकत्ता और कभी बम्बई से कि बारिश हुई या नहीं ? एक दिन मैं पूछ बैठा कि जैन साहब आप तो दुकान करते हैं, बारिश से तुम्हारा क्या संबंध है । इस पर उन्होंने कहा कि अरे भाई, भाव तो इसी से तय होते हैं कि कहां बारिश हुई और कहां सूखा पड़ा । तब मेरी समझ में यह बात आई कि व्यापारी बारिश की बात क्यों पूछता है, सूखा की बात क्यों पूछता है । बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं । बचपन में एक चौपाई गाया करते थे :

"खेती करे न बंज को जाए,

बुद्धि के बल बैठे खाए ।"

न खेती करें और न व्यापार करें, केवल बुद्धि के बल पर बैठकर लोग खाते हैं । ऐसे बहुत से बुद्धिजीवी हैं । ये श्रम का शोषण किए हुए हैं, जो व्यापार पर छाए हुए हैं और जो सच्चाई है वह यह है कि हमारे कर्मचारियों में भी, मैं सब को नहीं कहना चाहता, बहुतों के उदाहरण दे चुके हैं जो जनता से मिल करके काम करते हैं । हमारी अच्छी योजनाओं को सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी जनता तक सही रूप में नहीं पहुंचा पाते । वे भी उसमें से कुछ मुनाफा या मुआवजा लेना चाहते हैं । मुनाफा या मुआवजा उसको मिल रहा है जो ज्यादा मेहनत नहीं करता, जो पसीना नहीं बहाता है । अगर हम मेहनत और मुनाफा वहां तक पहुंचा दें जिसके लोग मुसतहक हैं तो मैं समझता हूं कि महंगाई पर बहुत बड़ा असर हो जाएगा । किसान कभी-कभी पैदावार बढ़ाकर सोचता है कि ज्यादा पैदावार बढाने से दाम कम हो जाते हैं । उसके अन्दर यह भावना क्यों है? फिर किसान पैदावार बढ़ाता है तो उसकी खरीद की चीजों के दाम क्या हैं इसके बारे में सोचना चाहिए । चाहे खाद हो, बिजली की दरें हों, चाहे मशीनरी हो, किसान जो पैदा करता है उसकी खरीद के दाम भी तय नहीं हैं । उसको उचित दाम पर मशीनरी नहीं मिलती, उचित दाम पर खाद नहीं मिलती, दवाइयां उचित दाम पर नहीं मिलतीं, चाहे मवेशी की दवाइयां हों, चाहे फसलों की दवाइयां हों, किसान को उचित दाम पर उसकी खरीद की चीजें नहीं मिलती हैं । हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि किसान जो पैदा करता है वह पैदा करने वाला है यह धारणा बनी हुई है कि किसान उत्पादक है, मैं भी यह मानता हूं लेकिन किसान साथ में उपभोक्ता भी है और इस देश का किसान सब से ज्यादा चीजें खरीदता है । .... वह खरीद की चीजें क्या हैं, इसको कोई नहीं सोचता । एक दाना खाता है, हजार दाना पैदा करता है, अजीब-अजीब कहानियां हिन्दुस्तान के किसान के बारे में लोगों ने बना रखी हैं । किसान हमारे मारे-मारे हो गये, लाचार हो गये । मेरे यहां एक फाइनेंस सेक्रेटरी बिले एक बार एक कमेटी में कह गए कि किसान के पास इतना माल है कि नोटों के छप्पर में वह आग लगाता है । मैंने उनसे कहा बिले साहब वह गांव आप मुझे बताएंगे, जहां किसान ने नोटों के छप्पर में आग लगाई हो । अजीब-अजीब कहानियां किसान के बारे में सोची हुई हैं ।

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि पैदा करने वाला किसान और मजदूर जो है, उसको आप साधन और सम्मान दें तो इस देश की पैदावार और बढ़ेगी । वितरण-व्यवस्था सही रखो । वितरण व्यवस्था अगर सही नहीं है, तब भी जरा दिक्कत हो जाती है । विलासिता की चीजें कितनी महंगी हो गईं, इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं । विलासिता की चीजें और महंगी हों । विलासिता की चीजों में माफ करना कुछ हमारी बहनों के लिये श्रृंगार की चीजें होती हैं ... **(व्यवधान)** ...

एक माननीय सदस्य :सिगरेट भी मंहगी हो गयी है ...

श्री राम चन्द्र विकल : सिगरेट और शराब कितनी महंगी हो जायें, सिनेमा का टिकट कितना महंगा हो जाय । यह तो वह सब लोग लेते हैं, जिनके पास अपार पैसा है । गरीब को तो भोजन, वस्त्र और दवाइयां मिल जायें, यही जरूरी है । विलासिता की चीजों की ओर कीमत बढ़े । एक सज्जन सिगरेट की बात कर रहे थे--

[श्री राम चन्द्र विकल]

सिगरेट मंहगी खरीदनी पड़ती है। मैं तो कहूंगा कि सिगरेट बिलकुल ही छोड़ दें। इससे गला खराब होता है, गले का केन्सर हो जाता है। न पियें तो अच्छा है। तो विलासिता की चीजें शौक से मंहगी हो जायं। लेकिन मैं तो हमेशा इसी बात का हूं कि खाद्य-सामग्री, जरूरी वस्तुएं सस्ती हों और पैदा करने वालों को साधन और सम्मान दिया जाय। इससे देश में पैदावार और खुशहाली होगी।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि सारे दिन इस विषय पर बहस कराने का मौका दिया और इस पर एक गंभीर चिंतन, राष्ट्रीय चिंतन हुआ है। हमारे विरोधी पक्ष की तरफ से भी काफी अच्छे सुझाव आए हैं। हमारी डेमोक्रेसी को चलाने का यह एक अच्छा उपाय है कि सरकार की कोई अच्छी बात हो, उसका विरोधी पक्ष को समर्थन करना चाहिए, दिल खोलकर समर्थन करना चाहिए और विरोधी पक्ष की तरफ से जो अच्छे सुझाव हों, उनको हमारी सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिये। तभी हमारी डेमोक्रेसी सही चलेगी और समाज का कार्य सही चलेगा। हमारी वितरण व्यवस्था और देश की आर्थिक व्यवस्था भी सही होगी।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार मानता हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: Hon. Minister.

SHRI K. P. SINGH DEO: How much time do I have, Madam?

SHRI PARVATHANENI UPENDRA (Andhra Pradesh): If you can reduce the prices, you can have as much time as you like.

SHRI K. P. SINGH DEO: That I cannot guarantee.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI1: There is no restriction for you.

SHRI S. W. DHABE: Ho,w can there be a time limit for you?

PROF. C. LAKSHMANNA: We only want a limit for the prices.

SHRI K. P. SINGH DEO: First of all, Madam, I am extremely grateful to the hon. Members of both the sides for their keen interest in this subject which, as they have already mentioned, is a very important subject because it hits every single Indian, every single consumer and it has an overall effect not only on the economy but also the production of various commodities, including the essential commodities. It has also a bearing on the economy of the country as well as *on* our policies, plans and programmes.

I would like, at the outset, to state that the points made by the hon. Members will be given highest consideration and we shall examine them in the letter and spirit in which they have enounciated them here and whoever practicable, we shall try to benefit from their points.

Practically, all shades of opinion from both sides of the House have been started and Members have given their inferences, observations and drawn conclusions according to their shades of opinion and the ideological concepts which they follow. Therefore, that also has to be taken into consideration.

The debate started off as a Calling-Attention motion on the situation arising out of the steep rise in prices of essential commodities, but in the wisdom of the Chairman of the House the entire gamut of rise in prices was to be discussed and in the process the entire planning process and the political philosophy and whatever takes place during elections was also brought in. I shall try to confine myself. Madam?, to the main essential commodities and, wherever possible, shall try to meet the various points which are relevant to the subject, but

wherever debating points have been sought to be scored, I shall try to avoid them.

As I have mentioned at the outset, there had been improvement in the price situation in 1984-85 over 1983-84 and I have also given the figures. Prof. Lakshmanna wanted to know why all the rise in the prices which has been stated in some documents, which also I have admitted to a certain extent. What I had mentioned was that the wholesale price index has moved on two per cent during the last 13 weeks, and this is brone out by figures—and I have checked it up as he had wanted me to check it up. In fact, the wholesale price index is 358.7 at the week ending 2nd November 1985 as compared to 365.9 on 3rd of August. So. there is no variation in what I have said in my opening remarks, and this I say after checking up.

While Mr. Chaturanan Mishra was speaking on the abnormal situation which is being created, there was a mild walk-out including his own leader, Mr. Kalyanasundaram. I don't know whether it was in protest against . . .

SHRI M. KALYANASUNDARAM (Tamil Nadu): It was suddenly imposed on us by the Chairman.

SHRI K. P. SINGH DEO: I don't know what was going on in your mind. I can only infer like the hon. Members have been inferring from various situations. You walked out at a time when your own Member was speaking. So, I don't know whether it was due to something from the Chair or something that the Member was saying. Anyway, I leave it to the imagination of the honourable House.

PROP. C. LAKSHMANNA: That was before the Member spoke.

SHRI K. P. SINGH DEO: He had also mentioned the question of surpluses and lack of godowns, that procurement has been good but there has been price rise. He also mentioned that in the public distribution system there has been a shortfall as compared to 1982, that in 1983 there was a shortfall and that those who are not covered by the public distribution system are not vocal and so, the Government is not afraid of them and those who are not covered by the PDS should be given a diffren-tial living index. Then he mentioned about capitalitistic society and the system and, at the same time, it was quite surprising, coming as it did from Shri Chaturanan Mishra belonging to the party which he does, to suggest that we should import some mechanism of the American type. I do not know whether he is still suffering from the PL-480 syndrome. But it did come as a surprise to me, especially when he also mentioned, in the same breath, about boycotting of foreign jjoods during the freedom struggle. So, I was a b<t cpnfused whether he was being ironical or whether he was serious about importing American high technology.

SHRI CHATURANAN MISHRA: If you like, I can clarify it.

SHRI K. P. SINGH DEO: I think, when you were speaking, I did not interrupt; I gave a patient hearing. I allowed you to draw your own conclusions, your own inferences and make your own observations.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: But you are provoking him now to reply.

SHRI K. P. SINGH DEO: I did not get provoked. Why should he get provoked?; I do not think, my intention is to provoke him at all.

SHRI S. W. DHABE: The intention is obvious.

SHRI K. P. SINGH DEO: Then, he also wanted to know why sugar prices have been increased -and why vanaspati prices have been increasing. He mentioned about coconut oil.

[Shri K. P. Singh Deo]

jute. And he also mentioned about the market forces being allowed to function and that, therefore, the prices were increasing. He also mentioned about artificial scarcity being created by the suppliers and that, therefore, the prices were going up. At a time when there is food in plenty, I do not think there is any artificial scarcity. If he points out the specific areas, we could examine where such artificial scarcity was prevalent. And we should like to take stringent and punitive action there through the help of the State Governments.

Then he mentioned about foreign trade, the policy being disastrous. The present policy which we are following, he claimed, was disastrous and that blackmarketeers and smugglers were having a field day. Then he again came back to having a dual pricing index and a living index for the poor farmers and the people under the public distribution system. And then he also mentioned that the wholesale trade should be nationalised.

Then, Shrimati Kanak Mukherjee mentioned the "Ancient Mariner", "Water, water everywhere, but not a drop to drink". Well. I do. not think that is an appropriate analogy of what we have. That is not exactly the position. There is no dearth of the availability of foodgrains anywhere in any of the States. We have just had a review held here in Delhi of the entire public distribution system where all the State Food Ministers and the Civil Supplies Ministers were present just before the session of Parliament. There have been certain drawbacks or delays in certain movements, but there has been no complaint of any non-availability of food anywhere, in any of the areas.

SHRIMATI KANAK MUKHERJEE: People do not have the purchasing power. That was my point.

SHRI K. P. SINGH DEO: She said, people were starving. She said, she had seen reports in some of the news magazines and papers. I think, she was referring to the article in the "INDIA TODAY" which we have seen because I could see the language being used was that of a quotation from the "INDIA TODAY".

SHRIMATI KANAK MUKHERJEE: I did quote from the "INDIA TODAY".

SHRI K. P. SINGH DEO: She mentioned also that there was no involvement of the majority of the people. She was also quite ironical about the scientific achievements. She said that there was no use of having the Arya-bhata and such type of developments when we had to solve other problems. She also said in the same strain, as Shri Mishraji, about western capitalism and feudal agencies. The line of approach was the same.

Shri Mukhtiar Singh Malik also said certain things about sugar magnates and vanaspati magnates getting concessions.

Then, Shri Gurupadaswamy also made the same points. He wanted the price front as well as the economic front to be tackled. He said that the statement was a camouflage to concede defects and difficulties and. therefore, he wanted clarifications. Then Shri Patil and Shri Rameshwar Thakur have adequately replied to his points and his philosophy.

Then Shri Rafique Alam mentioned about jute growers. We will take a look into that matter. Then Prof. Lakshmanna, I have already mentioned. Shri Gurupadasamy is not here. He informed me that he will be attending an important meeting. Dr. Shyami Sundar Mohapatra, I am glad he is here. He spoke very eloquently and wanted the House to believe that because we could not sell our wheat anywhere and that is why -we

are dumping it on the poor scheduled castes, scheduled tribes and the weaker sections of the society. Yet after giving a compliment to our young and dynamic Prime Minister which he mentioned as such in the same breath, he said that we are just dumping this wheat as there is no way out to sell. This could not be more far from the truth.

If I were *to* quote some excerpts from the Finance Minister's statement made yesterday in this House on the measures to be taken in the context of the surplus food, he opined:

> "The House is aware of the com mitment of this Government to the amelioration of the lot of the weaker and the vulnerable sections of the society. Then Annual Plan for 1985-86 and the Seventh Five Year Plan as approved recently by the National Development Council fully reflect our concern for the welfare of these sections."

Not only the Seventh Plan but the two previous plans—4th Plan and 6th Plan were all committed for amelioration of the weaker sections of the society. The RLGEP and NREP which went up by another name—food for work programme as well as getting under cover more and more people in creating permanent assets in the rural areas through these programmes is sought to be done by this very scheme which was announced yesterday. To pooh-pooh the idea that we are just dumping this wheat on poor, unfortunate tribals, weaker sections and more vulnerable sections of the society, I think, is very unkind to them: as well as to the Government.

The point made by Shri Mishra for having preferential or differential rate*—as hon Members are aware that —<-it will be sold to the weaker sections of -the society at Rs. 1.50 per kg. as is being done in the NREP and RLGEP. Otherwise, it will upset the food for work programme if we sell it at a lesser price. It will be sold in the open market at Rs. 1.75 per kg. to the ration card holders. They can even take unlimited stocks. As I said earlier, the Food and Civil Supplies Ministers from, the States had come to Delhi to attend ' the Advisory Committee meeting. There also it was strassed that the very fact of the public distribution system must be strengthened and expanded. In the Seventh Five Year Plan also, it has been mentioned in the Finance Minister's statemet and] would not like to go over it again. In the Seventh Plan adequate provision has been made for not only strengthening the public distribution system, but also augmenting it to have a wider coverage so that the price mechanism is -maintained by the Government and in the public distribution system, since it has to be implemented by the State Governmtants, the State Governments are being helped in number of ways and a number of steps have been taken to help the State Governments to improve the public distribution system. Sonne of them have been included in the Seventh Plan and discussions are also going on with them so that not only the public distribution system will be strengthened but punitive and deterrent action will also be taken under the Essential Commodities Act against people who are indulging in unfair trade practices, profiteering and black marketing which I think is the essence of the suggestion of the hon'ble members of both sides. There is no quarrel as far as that is concerned. Apart from wheat, there are predominantly rice eating areas also. There also the Finance Minister has come out with the scheme with which other concerned Ministries will also be associated and even rice will be sold at subsidised rates. Now the question of exports which had been raised. Our Prime Minister has made it abundantly clear and Government has taken a deliberate decision that

[Shri K. P. Singh Deo]

we will export but not at a price lower than what is being offered to our people i.e., less than the issue price which is Rs. 1.72 paise "and it will only be exported under conditions where we would require equal value of commodities which will help in our food production i.e. in a way to achieve self-sufficiency and self-reliance even in the food front.

Now, the twin objectives of self-sufficiency and self-reliance has been the corner stone and the emphasis has been on them in all our plans as far as food is concerned.(*(Interruptions).* You have the figures. You know, whether we are in a position to export food. Whether we are self-sufficient or not, it is for you to infer from this.

SHRI SUSHIL CHAND MOHUNTA: Why are you harping on this twin objective?

SHRI K. P. SINGH DEO: May I say what I would like to say? I have been hearing what you have to say or your colleagues have had to say. Why don't you allow me what I want to say or I have to say what you want me to say. Now so much has been said about the price rise of the essential commodities. The main reason for our taking a deliberate decision to allow price rise in these essential commodities i.e. sugar paddy, wheat, as well as edible oils is the question of our increasing production, giving incentive to farmers to get a remunerative price which will help in our overall production, in reducing our import of various commodities like essential oils, edible oils as well as sugar which we had to resort to because of the unremiu-nerative price in the sugar cane field which had brought down the acreage of sugar cane by more than 13 per cer<t and the availability o,f sugarcane for sugar crushing by diversion to other fields. Therefore, as recommended by the Commission on Agriculture Cost andi Prices, the rate for the statutory minimum price which is always linked with the public distribution and the price structure. We have agreed with the recommendations of the CACP in having Rs. 16.50 per quintal rate of sugarcane and to improve the liquidity of the millers so that there is more money available for them to purchase and give to the farmers at about Rs. 24 per quintal. Because the State-advised prices are higher than the statutory minimum prices and also what is available in the market. That is why the levy percentage was reduced from 65 per cent to 55 per cent. I will give a simple calculation, Madam. Our monthly requirement of sugar under the public distribution system is 3.13 lakh tonnes. Now annually that comes to a little more than 37 lakh tonnes. In addition we have to festivals, and we have the defence requirements. It all adds to about 40 lakh tonnes. Our production was a little more than 60 lakh tonnes. The ratio of 40 to 60 is 2:3. Therefore, it was 65 and 35 per cent; that is, levy sugar 65 per cent and non-levy or open market sugar 35 per cent. This year due to various measures taken by the States Governments and the Central Government fof~ increasing sugarcane production as well as sugar production such as modernisation of mills, to which some hon. Members referred—I think someone from the AIADMK mentioned it—the production is expected to be higher. From the Sugar Development Fund we are also giving funds for the modernisation of sugar mills so that the efficiency increases and the recovery also improves. Therefore, we are expecting about and more than 65 lakh tonnes this year and we hope to reach the peak figures of 1982-83 and 1983-84 in the coming years. Therefore, for the first time, we have taken the opportunity of declaring the price even for the next year, that is, Rs. 17 per quintal of sugarcane. Since there will be more production, and the requirement is only about 40 lakh tonnes, this can be net by a percen-

tage ratio of 55 to 45. And with easier availability of sugar in the open market, there will be more liquidity with the mills and prompt payments to farmers. Therefore, the farmers, the producers, for whom all sections of the House are most concerned, would be able to get encouragement and incentive for more production and there will be no diversion of sugarcane to other things.

The same is the case with edible oils also. I think the hon. Members would like us to be self-reliant rather than fall into the import trap. Wherever there is shortage in our production, we have to meet the consumption or the demand position by selective imports. This can at best be a temporary measure because I don't think it would be desirable for the country, nor is it financially possible for the country, to always depend on this import, when our vital foreign exchange has also to be conserved. Therefore, we have taken a deliberate decision, considered decision, that to help the indigenous farmers, we must not only bring down the import content of the edible oil from, 60 to 50 per cent, but we must also _ raise the price of mustard, groundnut and every other oil seeds and the oil$_s$ which go into the making of vanaspati and other edible oils. Therefore, it is a deliberate decision to encourage the farmers at one end and secondly, to reduce our import liabilities so that the country is in a better financial condition. I don't think there is any short-cut to achieving this nor is there any easier way of getting out of this syndrome. We shall have to suffer for some time. If we have to reach selfsufficient, if we have to reach self-reliance on our own steam, I think we shall have to tighten our belts. Therefore, we have also to give incentive and encouragement to the producer who is the farmer.

In regard to wheat and rice the same ethos is there. We are trying to develop better areas for edible oils so that we reach self-sufficiency. In the Seventh Plan the thrust is on developing' the eastern region and other regions as was done for wheat which became a bumper crop because of the support price which the Government had deliberately taken to encourage wheat production, the same is the case now that in the Seventh Plan period the Government has taken a concerted action and a deliberate decision to encourage pulses, edible oil-seed prices and indigenous edible oil and other cash crops so that the farmers are encouraged into going in for other cash crops also. These are the twin objectives why we have taken a conscious decision of raising the prices of some of the commodities at this stage so that the farmers are in a better position to know what the prospects of their agricultural products will be, whether it will be remunerative to them, whether it will be worthwhile for them to go in for a particular crop so that they achieve self-sufficiency and self-reliance in that held.

Shri Chaturanan Mishra asked why the PDS has come down. It was for the simple fact that in 1982-83 there was a severe drought for which there was more than the usual off-take of the PDS and in 1983-84 because of good harvest and good crop the availability of foodgrains improved and foodgrains was available in the open market and, therefore, the PDS also came down.

Shrimati Mukherjee had said that she had to pay Rs. 7.80 for sugar. The average price at which sugar is available in Delhi is Rs. 7.30 because of certain octroi and other taxes—sugar comes to Delhi from U.P. If the honourable Member paid more than the price at which it should be available, if she could give me the details we would like to have it looked into . . .

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: V/ill you return the money?

SHRI K. P. SINGH DEO: I may not be able to return the money, but I shall certainly have it examined since you want us to examine it and find out why it happened . . .

SHRIMATI KANAK MUKHERJEE. Actually it was my neighbour who bought 20 kgs for a function in his house, at the rate of Rs. 7.80 and he showed me the receipt.

SHRI K. P. SINGH DEO: If I could have the details, we shall see what action can be taken.

One honourable Member asked why the per capita availability of some of the important items of consumption has gone down. On the contrary, the per capita availability of some of the important items of consumption like cereals, edible oils, sugar, cloth and tea, has gone up. In 1977 cereals 386.4, in 1984 it was 442.1; edible oils 4.1, now 6.1; sugar 6.2 kgs. then, now it is 10.1 kg3.; cloth (metric) 13.8 metres then, now it is 14.7; tea 469 then and it is 565 now. This is inspire of the phenomenal rise in our population. The availability and the offtake also imiproved. The purchas-[The Deputy Chairman in the Chair] ing power of the people has also improved. While the Plan discussion was on at the NDC, the Prime Minister in his address also mentioned that the percentage of people living below the poverty line in the last five years has reduced from 47 per cent to 36 per cent and the thrust of this Five Year Plan is to bring it down even to 25 per cent.

5 P.M.

Madam, just one point before 1 conclude and it is this that a concerted effort has been made and a deliberate strategy has been adopted to encourage the edible oil producers, the indigenous edible oil producers, to get a miore remunerative price because the common people, especially the weaker sections of the society, use that medium rather than the other and more expensive medium.

SHRI S. W. DHABE: The coconut prices are falling in Kerala.

SHRI K. P. SINGH DEO: Therefore, these are the two main features in which the entire price rise has to be viewed and I am sure that the honourable House will agree with me that with this twin strategy of helping the farmer, which is also the suggestion of the honourable Members, and reducing the import, which is again the suggestion of honourable Members, and with a better and wider public distribution system, we would be able to meet the situation.

SHRI S. W. DHABE: You see, the prices of coconut have come down in Kerala.

Shri K. P. Singh Deo the points made by the honourable Members is that the stocks do not appear in the shops and the traders are selling them to the wholesale traders instead of bringing them to the fair price shops. This will be strictly monitored and this is what exactly we have addressed the State Governments about because it is their duty to see that the public distribution system in the States functions properly especially in the tribal areas and the remote areas. Therefore, we have taken the concerted decision yesterday that where the State Governments do not have the requisite agencies, we would like to helo them in that and even alternative agencies can be pressed into service so that the State Governments are enabled to manage them properly and we will also take punitive and deterrent action against those who are indulging in unfair trade practices. Thank you, Madam.

SHRI S. W. DHABE: I would like to tell the Minister that in Kerala the prices of coconut have come down and they have come down from Rs. 4 to Rs. 2.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: He is dealing with price rise and not fall in prices!

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we shall take up Special Mentions. Yes, Mr. Ashwani Kumar.

REFERENCE TO THE SMUGGLING OF URANIUM ORE

श्री अश्विनी कुमार (बिहार) : माननीया उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान यूरेनियम और चोरी में जो घपला हो रहा है, चोरी हो रही है उसको दबाने के लिए जो षडयंत्र रचा जा रहा है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके पहले भी सदन में कई बार चर्चा हुई है कि बिहार की जादूगोड़ा माइंस से यूरेनियम और स्मगल कर के नेपाल भेजा जाता है ओपन बार्डर से वहां से विददेशों में जाता है जो हमारे शत्रु देश हैं चीन और पाकिस्तान को भेजा जाता है। अभी एक घटना 15-7-85 को हुई जिसमें पांच किलो यूरेनियम ओर जाते हुए फारबिसगंज पूर्णिया जिले की पुलिस ने जा कर उसको पकड़ा और अपराधियों को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया। मैं यहां पर वहां के एस. पी. का जो वक्तव्य है उसको आपके सामने रखना चाहता हूं।

'उपलब्ध साक्ष्य से ऐसा ज्ञान पड़ता है कि जादूगोड़ा खान के स्थानीय कर्मचारियों की सांठगांठ से काफी मात्रा में कच्चे यूरेनियम की चोरी करने के बाद आपराधिक षडयंत्र तथा अधिक धन कमाने के लोभ में यूरेनियम जैसे बहुमूल्य पदार्थों की तस्करी की कार्यवाई की गयी जिसे नेपाल के माध्यम द्वारा राष्ट्रीय हित के विरुद्ध पाकिस्तान तथा चीन भेजे जाने की योजना थी'।

उसमें लोग पकड़े गये और उसके बाद उसमें लिखा है कि –

'इन फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी स्थानीय पुलिस के सहयोग से शीघ्र की जाए तथा गिरफ्तार होने पर विशेष शाखा के पदाधिकारियों के सहयोग से तस्करों और अन्य सहयोगियों के संबंध में गहन पूछताछ करने की आवश्यकता है। (2) जब्त किये गये कच्चे यूरेनियम के नमूने की शीघ्र जांच हेतु अनुसंधान विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजना चाहिए'।

अभियुक्तों के ब्यान से यह तय हुआ था कि चोरी करने के बाद चोरी किया हुआ माल जादूगोड़ा खान से आया है। यह सब होने के बाद ... एस. पी. ने यह निवेदन किया कि सी. बी. आई. को जांच देकर किया जाना चाहिए। परन्तु सी.बी.आई. को देने की बजाय बिहार सरकार की अपराध और अनुसंधान शाखा ने एक साधारण इंस्पेक्टर को उसके लिए भेजा और इंस्पेक्टर ने वह यूरेनियम जो था वह अपने कब्जे में करके पटना उसको ले आया और उस इंस्पेक्टर ने घोषणा कर दी कि यह यूरेनियम ओर नहीं है यह मिट्टी है। एक इंसपक्टर जिसको कि कैमिकल एनेलिसिस का पता नहीं वह यूरेनियम ओर को मिट्टी कैसे घोषित कर सकता है। इसके पीछे क्या हो सकता है? यह विशेष विषय है। जबकि उन्होंने बताया था, जो अपराधी पकड़े गये थे, कि 2,81,000 रुपये किलो यह माल बिकने वाला है। नेपाल में किसको भेजा जायेगा उन सबके नाम बताये परंतु ऐसे साधारण व्यक्ति को देकर उसको हुश अप करने का केस हो रहा है। यह कई वर्षों से चल रहा है और हमारी बगल में जो हमारा पड़ोसी देश है वह हमारे ही यूरेनियम से हमारे खिलाफ बम बनाने का षडयंत्र कर रहा है और बिहार की अपराध शाखा सो रही है। एक बड़े अधिकारी को भेजने की बजाय, सी. बी. आई. को इन्क्वायरी देने की बजाय एक साधारण इंस्पेक्टर को भेजा गया जिसने यह घोषणा की कि वह मिट्टी थी। मिट्टी होती तो पूर्णिया की पुलिस क्यों पड़ती, एस. पी. क्यों लिखते? इसके पीछे विशेष षडयंत्र है और मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस मामले की तुरंत छानबीन की जाये और सारे अपराधियों को पकड़ा जाये और जिस हल्के ढंग से इस इंक्वायरी